● वर्ष-2
● अंक-185
रायपुर, रविवार
26 मार्च 2023
● पृष्ठ-6
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmailĐcom

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

अवकाश सूचना

समाचार पचीसा के कार्यलय में 26 मार्च रविवार अवकाश रहेगा। समाचार पत्र का अगला अंक 28 मार्च मंगलवार को प्रकाशित होगा।

फिर मंडरा रहा कोरोना का खतरा

बढ़ते मामलों के बीच 10-11 अप्रैल को राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल

नई दिल्ली। देश में एक बार फिर कोविड-19 और मौसमी इन्फ्लुएंजा के मामले बढ़ने लगे हैं। इस बीच सरकार अस्पतालों की तैयारियों का जायजा लेने के लिए 10 और 11 अप्रैल को राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल की योजना बना रही है। इसे लेकर केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि सभी जिलों के सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की स्वास्थ्य इकाइयां इस मॉकड्रिल में भाग लेंगे। एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि 27 मार्च को होने वाली वर्चुअल मीटिंग में मॉक ड्रिल के सटीक विवरण के बारे में राज्यों को जानकारी दी जाएगी।

दरअसल, पिछले 24 घंटे में 1590 लोगों में संक्रमण की पुष्टि की गई है। इस दौरान छह संक्रमितों की मौत भी हुई है। 146 दिनों में यह कोरोना के एक दिन का सबसे अधिक केस है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक, पिछले पांच हफ्तों में देश में संक्रमण के मामलों में नौ गुना तक बढ़ोतरी आई है। संक्रमण के

बढ़ते जोखिम को देखते हुए मंत्रालय ने सभी राज्यों को सलाह दी कि वे कोविड से मुकाबले के लिए चार टी और कोविड उपयुक्त व्यवहार के पालन पर विशेष ध्यान दें।

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण और आईसीएमआर के महानिदेशक डॉ राजीव बहल द्वारा जारी की गई एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि फरवरी के मध्य से देश में कोविड-19 मामलों में क्रमिक लेकिन निरंतर वृद्धि देखी जा रही है। इस समय, देश में अधिकांश कोरोना मामले केरल (26.4 प्रतिशत), महाराष्ट्र (21.7 प्रतिशत), गुजरात (13.9 प्रतिशत), कर्नाटक (8.6 प्रतिशत) और तमिलनाडु (6.3 प्रतिशत) जैसे कुछ राज्यों द्वारा रिपोर्ट किए जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा शनिवार को जारी एक संयुक्त एडवाइजरी में कहा गया है कि पिछले कई हफ्तों में कुछ राज्यों में कोविड-19 की टेस्टिंग में गिरावट आई है। साथ ही यह भी पाया गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित मानकों की तुलना में वर्तमान में परीक्षण स्तर अपर्याप्त हैं। इसको देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और आईसीएमआर ने सभी राज्यों को कोरोना जांच में बढ़ावा देने और लक्षणों की जानकारी देने के लिए भी कहा है। इसके अलावा कोरोना के बढ़ते मामलों से निपटने की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मॉकड्रिल में सभी राज्यों को शामिल होने के लिए भी कहा गया है। अप्रैल की 10 और 11 तारीख को होने वाली मॉकड्रिल में आईसीयू बेड, मेडिकल इक्विपमेंट्स, ऑक्सीजन और मैनपावर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।

लॉन्ग कोविड में अजीबो-गरीब लक्षण

कोरोना वायरस का संक्रमण, रोग के दौरान और ठीक होने के बाद भी लोगों के लिए कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बना हुआ है। संक्रमण से ठीक होने के बाद भी लोगों में लंबे समय तक कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं देखी जा रही हैं। लॉन्ग कोविड या पोस्ट कोविड के अधिकतर मामलों में थकान-कमजोरी, कुछ लोगों को सांस फूलने, ब्लड प्रेशर और हृदय रोगों से संबंधित दिक्कतें भी महसूस हुईं। पर हाल ही में स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कुछ रोगियों में लॉन्ग कोविड में अजीबो-गरीब लक्षण देखे हैं। ऐसे रोगियों को लोगों के चेहरे पहचानने में दिक्कत हो रही है। लॉन्ग कोविड में फेस ब्लाइंडनेस की समस्या में लोगों को अपने करीबों लोगों को पहचानने में दिक्कत हो रही है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने इसे न्यूरोलॉजिकल समस्या के तौर पर वर्गीकृत किया है, जिससे स्पष्ट होता है कि कोरोना वायरस दीर्घकालिक तौर पर न्यूरोलॉजिकल विकारों को भी बढ़ावा दे रहा है।

अमेरिकन मीडिया में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार कोरोना संक्रमण का शिकार रहे कई लोगों ने कुछ वर्षों बाद अपने परिवार के लोगों को पहचानने में कठिनाई होने की शिकायत की है। इसमें रोगियों को आवाज तो समझ आ रही है पर वह चेहरे से मैच नहीं कर रहा। एक रोगी का जिक्र करते हुए शोधकर्ताओं ने बताया- रोगी के मुताबिक ऐसे लग रहा था जैसे उसके पिताजी की आवाज़ किसी अजनबी के चेहरे से निकल रही थी।

साइंस डायरेक्ट जर्नल में शोधकर्ता कहते हैं, अब तक माना जा रहा था कि कोविड-19 हृदय, फेफड़े, गुर्दे, त्वचा पर असर डाल रहा है पर लॉन्ग कोविड के रूप में कई लोगों में मस्तिष्क-न्यूरोलॉजिकल समस्याओं के बारे में भी पता चला है। लॉन्ग कोविड वाले लोगों में इस तरह की दिक्कतें लंबे समय बनी रह सकती हैं।

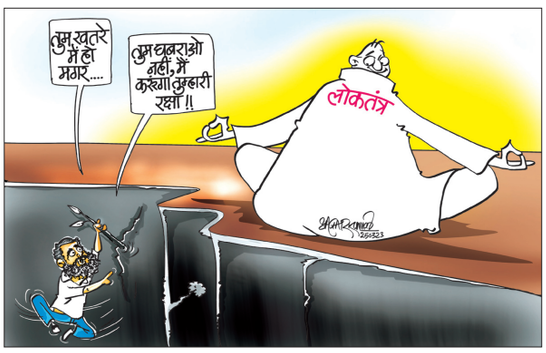

सावरकर पूरे देश के लिए एक आदर्श

कांग्रेस नेता ने उन्हें बदनाम किया- शिंदे

मुंबई। वीर सावरकर को लेकर देश की राजनीति लगातार गर्म रहती हैं। मानहानि मामले में दोषी पाए जाने के बाद राहुल गांधी को सूरत कोर्ट से 2 साल की सजा सुनाई गई। इसके बाद उनके लोकसभा सदस्यता भी रद्द कर दी गई। आज राहुल गांधी एक प्रेस को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उनसे माफी को लेकर सवाल पूछा गया। राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है और गांधी माफी नहीं मांगता। इसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे ने राहुल गांधी पर पलटवार किया है। एकनाथ शिंदे ने साफ तौर पर कहा है कि राहुल गांधी ने वीर सावरकर को हमेशा बदनाम किया है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने विधानसभा में कहा कि सावरकर केवल महाराष्ट्र के देवता नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक आदर्श हैं और राहुल गांधी ने उन्हें बदनाम किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की इस हरकत के लिए जितनी भी आलोचना की जाए कम होगी।

गृहमंत्री अमित शाह सीआरपीएफ के कार्यक्रम में हुए शामिल

नक्सल प्रभावित इलाकों में बढ़ा विकास, हिंसा में कमी : शाह

जगदलपुर। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश के सुरक्षाबलों ने वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ पिछले नौ सालों में एक मजबूत लड़ाई लड़ी है। इसमें सफलता भी मिली हैं। उन्होंने कहाकि, साल 2010 के उच्चतम स्तर के मुकाबले नक्सली हिंसा में 76% की कमी आई है। वहीं जान गंवाने वालों में करीब 78% की कमी आई है। उन्होंने कहा कि दशकों तक वामपंथी उग्रवाद के गढ़ रहे बिहार और झारखंड के बूढ़ा पहाड़, चक्रबंधा और पारसनाथ के क्षेत्रों को उग्रवाद से मुक्त किया गया है। केंदीय गृहमंत्री शनिवार को सीआरपीएफ के स्थापना दिवस समारोह में पहुंचे थे। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में हुए कार्यक्रम में शाह ने कहा कि, सीआरपीएफ ने अलग-अलग राज्यों की पुलिस के साथ मिलकर ज्वाइंट टास्क फोर्स बनाई। इससे वामपंथी उग्रवादियों को अंतरराज्यीय सीमाओं का लाभ उठाने से रोका जा सके। कहा कि, जो वामपंथी उग्रवादी जनजातीय क्षेत्रों के विकास में रोड़ा बने हुए थे, उन्हें हटाने का काम भी सीआरपीएफ ने किया है। समस्या वाले सभी क्षेत्रों में सीआरपीएफ ने स्थानीय पुलिस को साथ लेकर उनकी हौसला अफजाई करते हुए एक अभेद्य शक्ति का निर्माण किया और सामंजस्य के साथ अपने संगठन कौशल का भी परिचय दिया। शाह ने कहा कि, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में हिंसा में बहुत तेजी से कमी आई है। अब इन इलाकों में आखिरी व्यक्ति तक विकास पहुंच रहा है। बिहार और झारखंड में सुरक्षा का वैक्यूम समाप्ति की ओर है। यह सीआरपीएफ के वीर जवानों और पुलिस बलों के संयुक्त पराक्रम के कारण ही हो पाया है। उन्होंने कहा कि वामपंथी उग्रवादियों के फंडिंग स्रोत को रोकने के लिए एनआईए और ईडी की ओर से भी अनेक प्रकार के केस दर्ज कर हम कठोर कार्यवाही कर रहे हैं। मोदी सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्य वामपंथी उग्रवाद-प्रभावित क्षेत्रों में भी पहुंच रहे हैं।

नक्सल क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहा विकास : गृहमंत्री ने कहा कि, नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास के लिए स्वीकृत 70,000 किलोमीटर में से 11,000 किलोमीटर सड़क बन चुकी है। 2343 मोबाइल टावर लग चुके हैं, एकलव्य स्कूल को प्रायोरिटी एरिया में खोलने का काम चल रहा है। बैंकों की 1258 ब्रांच केवल पांच साल में खोली गई है, 1348 एटीएम खोले गए हैं।

सुकमा के नक्सली गांव में गृहमंत्री शाह की पाठशाला

छत्तीसगढ़ में सुकमा के नक्सल प्रभावित गांव पोटकपल्ली में शनिवार को गृहमंत्री अमित शाह की पाठशाला लगी। गृहमंत्री शाह गांव के एक सरकारी स्कूल में अचानक पहुंचे और बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। इस दौरान उन्होंने बच्चों से बातें की, उनको अंग्रेजी में जानवरों के नाम बताए और फिर जाते-जाते टॉफियां भी बांटी। अपना परिचय दिया, बच्चों का परिचय लिया। फिर बच्चों को पढ़ाने की शुरुआत हो गई। शाह ने क्लास रूप में टंगे चार्ट पर बने जानवरों को देखा और फिर एक-एक कर बच्चों को पास बुलाया। चार्ट पर बने चित्र पर उंगली रखते और बच्चों से उनके बारे में पूछते। बच्चे भी गृहमंत्री के सवालों का जवाब देते रहे। इस दौरान गृहमंत्री ने उन्हें अंग्रेजी में भी जानवरों के नाम बताए। थोड़ी ही देर की बातचीत में बच्चे भी गृहमंत्री शाह के साथ घुलमिल गए। उन्होंने भी जमकर बातें की। इससे पहले गृहमंत्री ने जगदलपुर में आदिवासी भाषा की पहली समाचार सेवा का भी शुभारंभ किया।

प्रमुख समाचार

झूठ बोलना राहुल गांधी की फितरत- रविशंकर प्रसाद

नई दिल्ली। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि राहुल पर मानहानि के 60 मामले चल रहे हैं।

बीजेपी सांसद रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आदत के मुताबिक भटकाने की कोशिश की, गलत बयानी की और विषय पर कुछ नहीं बोला। राहुल गांधी को 2019 में उनके भाषण पर सजा हुई है। आज उन्होंने कहा कि मैं सोच समझ कर बोलता हूं मतलब 2019 में जो राहुल गांधी ने बोला था वे सोच समझ कर बोला थे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अयोग्य करार दिए जाने वाले अकेले नेता नहीं हैं। बल्कि बीजेपी के 6 नेता सहित कुल 32 नेता अयोग्य करार दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को बलिदानी बताना चाहती है और कर्नाटक में राहुल गांधी को भुनाना चाहती है। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने गलत बयान देने की कोशिश की और इस विषय पर बात नहीं की। राहुल गांधी को 2019 में उनके भाषण की सजा मिली है। भाजपा नेता ने कहा कि राहुल गांधी ने फिर झूठ बोला कि उन्होंने लंदन में कुछ नहीं कहा।

यूके की टिप्पणी के लिए माफी मांग ली होती तो तो सांसदी छिनने की नौबत न आती-रामदास

नई दिल्ली। आठवले यूके में गांधी की टिप्पणियों के बारे में बात कर रहे थे जहां उन्होंने दावा किया था

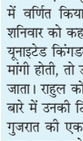

कि भारत अपने लोकतंत्र की बुनियादी संरचना पर हमले और देश के संस्थानों पर पूर्ण पैमाने पर हमले का सामना कर रहा था। उन्होंने ब्रिटिश सांसदों को यह भी बताया था कि विपक्षी नेताओं के माइक्रोफोन संसद में म्यूट कर दिए जाते हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को एक कट्टरपंथी और फासीवादी संगठन के रूप में वर्णित किया। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने शनिवार को कहा कि अगर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यूनाइटेड किंगडम में की गई टिप्पणी के लिए माफी मांगी होती, तो उन्हें लोकसभा से अयोग्य नहीं ठहराया जाता। राहुल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उपनाम के बारे में उनकी टिप्पणी के लिए मानहानि के मामले में गुजरात की एक अदालत द्वारा दो साल की जेल की सजा सुनाए जाने के एक दिन बाद अयोग्य घोषित कर दिया गया था। अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए आठवले ने कहा कि अगर राहुल गांधी ने यूके की टिप्पणी के लिए माफी मांग ली होती तो वो संसद सदस्यता नहीं गंवाते।

अमृतपाल साधु के भेष में दिल्ली में दिया दिखाई, अलर्ट जारी

चंडीगढ़। वारिस पंजाब दे के चीफ और खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह की आठवें दिन भी तलाश जारी है। अमृतपाल सिंह की तलाश में 6 राज्यों की पुलिस जुटी हुई है और आखिरी बार उसकी दिल्ली में होने की सूचना मिली थी। पंजाब पुलिस की कुछ टीमें शनिवार सुबह दिल्ली पहुंची। पुलिस के हाथ ड्रक्क्ष कश्मीरी गेट की कुछ ऐसी सीसीटीवी फुटेज लगी हैं जिसमें अमृतपाल को साधु के रूप में देखा गया है। इतना ही नहीं पुलिस बाकी सीसीटीवी कैमरे भी खंगाल रही है। इस वीडियो फुटेज को अभी रिलीज़ नहीं किया गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज में अमृतपाल सिंह साधु के भेष में नजर आया, इस जानकारी के बाद दिल्ली पुलिस और पंजाब पुलिस ने दिल्ली में जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया है। इसी के चलते इंडो-नेपाल बॉर्डर पर अमृतपाल और उसके साथियों के पोस्टर लगाए गए हैं और डॉग स्क्वॉड की मदद से तलाश जारी है। इतना ही नहीं इंडो-नेपाल के गौरीफंटा बॉर्डर पर अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस को शक है कि दिल्ली से अमृतपाल पड़ोसी राज्य नेपाल भागने की कोशिश कर सकता है।

संजय राउत की विवादित बयान, संसद सदस्यता खतरे में

मुंबई। शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत के विशेषाधिकार हनन नोटिस को महाराष्ट्र विधान परिषद की उपसभापति नीलम गोरहे ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को भेज दिया। संजय

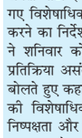

राउत के खिलाफ महाराष्ट्र विधानसभा में विधिमंडल (विधायिका) को चोरमंडल (चोरों का शरीर) कहने के लिए विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया गया था। इस महीने की शुरुआत में महाराष्ट्र परिषद के उपाध्यक्ष ने शिवसेना (यूबीटी) नेता को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा उनके खिलाफ दिए गए विशेषाधिकार हनन नोटिस का जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। हालांकि, नीलम गोरहे ने शनिवार को कहा कि राज्यसभा सांसद की प्रतिक्रिया असंतोषजनक थी। गोरहे ने परिषद में बोलते हुए कहा कि राउत ने अपने जवाब में सदन की विशेषाधिकार समिति की संरचना, इसकी निष्पक्षता और कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे। राज्यसभा के वरिष्ठ सदस्य होने के नाते यह उम्मीद नहीं की जाती कि वह (राउत) विशेषाधिकार समिति के कामकाज पर सवाल उठाएंगे। इसलिए मैं उनके जवाब से पूरी तरह सहमत नहीं हूं और मुझे यह संतोषजनक नहीं लगता।

लाई जा सकती है रेडियोएक्टिव सुनामी, उत्तर कोरिया ने लॉन्च किया अंडर-वॉटर न्यूक्लियर ड्रोन

नई दिल्ली। उत्तर कोरिया ने दावा किया कि उसने रेडियोएक्टिव सुनामी फैलाने में सक्षम अंडर वॉटर न्यूक्लियर ड्रोन का सफल परीक्षण किया है। इसकी जानकारी वहां की न्यूज एजेंसी केसीएनए ने दी। हाल ही में अमेरिका की ताकतवर फौज के साथ प्रदर्शन में नॉर्थ कोरिया के दुश्मन साउथ कोरिया की सेना ने युद्धाभ्यास किया था।प्योंगयांग ने इस सप्ताह जवाब में अपने स्वयं के सैन्य अभ्यास किए। आधिकारिक कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने कहा, जिसमें एक नए परमाणु-सक्षम अंडरवाटर ड्रोन का परीक्षण-फायरिंग भी शामिल है। ये एक ऐसा न्यूक्लियर ड्रोन है जो रेडियो एक्टिव सुनामी लाने के साथ ही दूसरे देशों के पोट्स को भी पलभर में तबाह कर सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नया हथियार, जिसे हाइल कहा जाता है, जिसकाअर्थ कोरियाई में सुनामी होता है। ये किसी भी तट और बंदरगाह पर तैनात किया जा सकता है। अंडर वॉटर न्यूक्लियर ड्रोन को साल 2012 से तैयार किया जा रहा था। पिछले दो सालों में इससे जुड़े 50 टेस्ट किए जा चुके थे। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने व्यक्तिगत रूप से परीक्षणों का निरीक्षण किया।

राहुल के बहाने कितनी कारगर है विपक्षी एकता की कोशिश?

अतुल सिन्हा

राहुल गांधी पर की गई कार्रवाइयों और उसके बाद उनके तेवरों ने एक बार फिर विपक्षी पार्टियों की एकता की उम्मीद जगाई है। खासकर तब जब सभी विपक्षी पार्टियों ने राहुल पर की गई कार्रवाई को गलत ठहराया है और मोदी सरकार पर सीधा निशाना साधा है। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कांफ्रेंस में जिस तरह यह कहा कि मोदी सरकार ने विपक्ष को इस बहाने एक मजबूत और कारगर हथियार दे दिया है, उससे यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या 2024 में कांग्रेस तमाम क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर मोदी के खिलाफ एक बड़े मोर्चे का हिस्सा बनेगी?

सीपीआई के महासचिव डी राजा मानते हैं कि विपक्षी एकता की कोशिशें तो अपने-अपने तरीके से चल ही रही है। कई राज्यों में और खासकर तमिलनाडु में कांग्रेस भाजपा विरोधी ताकतों के साथ है ही। ये हो सकता है कि केरल या पश्चिम बंगाल में थोड़ी मुश्किल आए, लेकिन जहां तक मोदी सरकार को हटाने के लिए एक व्यापक मोर्चे का सवाल है, हम चाहते हैं कि कांग्रेस को इस मौके का फायदा उठाना चाहिए और एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते एकता की कारगर पहल करनी चाहिए। उनका कहना है कि बेशक कांग्रेस विरोध की वजह से बहुत सारी विपक्षी पार्टियां बनीं और क्षेत्रीय दलों का भी अपने-अपने कारणों से उदय हुआ, लेकिन जो मौजूदा स्थिति है उसमें पहली प्राथमिकता मोदी सरकार को हटाना है और इसके लिए कांग्रेस को सबके साथ मिलकर एक मोर्चा बनाने की मजबूत पहल करनी चाहिए।

प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष और जाने-माने लेखक विभूति नारायण राय का भी कहना है कि इस वक्त कांग्रेस को सभी विपक्षी और क्षेत्रीय दलों को साथ लेकर चलने की जरूरत है। यह उचित मौका है और राहुल

गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने उनकी विश्वसनीयता और स्वीकार्यता जनता के बीच फिर से स्थापित की है। मोदी सरकार की ओर से की जा रही कार्रवाइयों ने भी उनके प्रति तमाम विपक्षी पार्टियों को नरम और सकारात्मक बना दिया है, ऐसे में ये तो तय है कि कांग्रेस को 'लीड' लेने की जरूरत है।

वामपंथी पार्टियों का रुख वैसे भी भाजपा की बढ़ती ताकत को देखते हुए पिछले करीब एक दशक से कांग्रेस के प्रति खासा नरम रहा है। मोदी राज के इन नौ सालों में कांग्रेस को आगे बढ़ाने में ये पार्टियां भी अपने-अपने तरीके से लगी हुई हैं। खासकर तब जब विपक्ष के पास कोई भी ऐसा मजबूत चेहरा नहीं है, जो मोदी को सीधे तौर पर टक्कर दे सके। ऐसे में राहुल गांधी जिस तरह से एक जुझारू नेता के तौर पर उभरे हैं और जमीनी स्तर पर लगातार मेहनत करते दिख रहे हैं, इससे अब विपक्षी पार्टियों की उम्मीद और बढ़ गई है।

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी राहुल को अयोग्य ठहराये जाने और केंद्र की ओर से तमाम संस्थाओं का सियासी इस्तेमाल करने को लेकर राहुल के समर्थन में हैं। वह कहते हैं कि कांग्रेस को समाजवादी पार्टी के साथ-साथ सभी विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। 2024 में मोदी राज का खात्मा भी तभी हो सकता है, जब आपसी अहंकार और द्वेष छोड़कर सब साथ आएं, अपनी ताकत और हैसियत को देखते हुए एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत इकट्ठे हों। ऐसा पहले भी हुआ है और तमाम बड़ी लड़ाइयां संसद से निकल कर सड़क पर लड़ी गई हैं, तभी बदलाव आया है।

लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रवक्ता अजय कुमार मानते हैं कि यह कानूनी मामला है और आगे की लड़ाई कानूनी तौर पर ही लड़ी जा सकती है। ऊपरी अदालत जो फैसला सुनाएगी, देखा जाएगा, फिलहाल तो जो हो रहा है कानूनी तौर पर सही ही है।

विपक्ष को साथ लेकर चलने की कवायद

भाजपा के खिलाफ विपक्षी एकता के लिए लंबे समय से प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक विपक्षी दलों को इस मुहिम में कोई ठोस कामयाबी नहीं मिल सकी है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के समापन पर कांग्रेस पार्टी ने कई दलों को श्रीनगर आने का न्योता दिया था, मगर दर्जनभर पार्टियां भी वहां नहीं पहुंच सकीं। इससे पहले ज्यादातर विपक्षी दलों ने यात्रा से दूरी बना रखी थी। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, केसीआर और शरद पवार जैसे कई नेता, तीसरे मोर्चे की संभावना तलाशते रहे।

सीएम नीतीश कुमार ने कांग्रेस पार्टी को यह सलाह दे दी, वे मिशन 2024 के लिए साथ मिलकर चुनाव लड़ने को लेकर जल्द ही कोई निर्णय करें। देखें, कहीं देर न हो जाए। कांग्रेस को जल्द फैसला लेना चाहिए। अगर कांग्रेस मेरा सुझाव मानकर साथ में लोकसभा चुनाव लड़ती है तो भाजपा का ग्राफ, सौ सीटों से भी नीचे आ सकता है। अब जैसे ही राहुल गांधी को मानहानि मामले में सजा हुई और उसके बाद उनकी सांसदी चले जाना, इस घटनाक्रम ने विपक्षी दलों को सकते में ला दिया है। इससे पहले इतने विपक्षी नेता, किसी एक मुद्दे पर साथ खड़े नजर नहीं आए थे। यहां तक कि कांग्रेस के पूर्व नेता कपिल सिब्बल भी राहुल के समर्थन में दिखाई पड़े। दूसरे विपक्षी दल भी कांग्रेस के साथ दिखे।

केंद्रीय गृह मंत्री ने राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा में सीआरपीएफ के योगदान की सराहना की

नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई अंतिम चरण में: शाह

जगदलपुर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को 84 वें सीआरपीएफ दिवस के अवसर पर देश की आंतरिक सुरक्षा में सीआरपीएफ के योगदान और सुरक्षित रूप से जिम्मेदारी निभाने के लिए सराहना की। 84वें सीआरपीएफ दिवस के मौके पर अपने संबोधन के दौरान शाह ने कहा, पहली बार किसी नक्सली इलाके में सीआरपीएफ दिवस मनाया जा रहा है। सीआरपीएफ ने देश की आंतरिक सुरक्षा में योगदान दिया है। राष्ट्र महिला सीआरपीएफ कर्मियों को सलाम करता है। सीआरपीएफ का योगदान है. महत्वपूर्ण। उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ ने देश में पिछले चुनावों के दौरान अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ ने नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और देश के कई इलाकों में उन्हें देर किया है। उन्होंने आगे कहा, लोकतंत्र तभी जीवित रह सकता है जब इसे विश्वसनीय तरीके से संरक्षित किया जाए। अन्य सीएपीएफ के साथ-साथ देश में शांतिपूर्ण चुनाव कराने में सीआरपीएफ का योगदान आवश्यक है। उन्होंने कहा, पिछले कई चुनावों में सीआरपीएफ कर्मियों ने हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुरक्षित रूप से संचालित करने की जिम्मेदारी निभाई है।

शाह ने शनिवार को छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में सीआरपीएफ जवानों को श्रद्धांजलि दी। छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने की संभावना है, जिसके लिए भाजपा ने आगामी चुनावों के प्रचार के लिए गति पकड़ ली है। छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान में शामिल सुरक्षा बलों को शुक्रवार को बड़ी सफलता मिली, सुकमा क्षेत्र में दो महिलाओं समेत 16 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि देश में वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई जीत के अंतिम चरण में नजर आ रही है और इसमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के जवानों के सर्वोच्च बलिदान का बहुत बड़ा योगदान है। सीआरपीएफ के 84वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए शाह ने बल से अनुरोध किया कि जब तक इस खतरे का पूरी तरह से सफाया नहीं हो जाता वे वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई बहादुरी से जारी रखें। नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई में सीआरपीएफ की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में विकास की राह में आने वाली बाधाओं को दूर करने का श्रेय सीआरपीएफ कर्मियों को जाता है।

शाह ने कहा, सीआरपीएफ ने वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ी और सभी मोर्चों पर सफलता हासिल की। बल ने स्थानीय पुलिस के साथ समन्वय स्थापित कर संगठनात्मक कौशल का भी उदाहरण पेश किया है। उन्होंने कहा कि 2010 की तुलना में देश में वामपंथी उग्रवादी हिंसा की घटनाओं में 76 फीसदी की कमी आई है और साथ ही जान हानि (आम लोग और सुरक्षा कर्मी) में भी 78 फीसदी की कमी आई है।

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की भूमिका का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों एजेंसियां वामपंथी उग्रवाद का वित्त पोषण रोकने के लिए सख्ती से काम कर रही हैं। शाह ने कहा कि सीआरपीएफ का वार्षिक उत्सव पहली बार वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है और यह भी छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में। बस्तर जिले के मुख्यालय जगदलपुर से लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित सीआरपीएफ कोबरा की 201वीं बटालियन के करनपुर शिविर में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। पिछले तीन दशकों से वामपंथी उग्रवाद से संघर्ष कर रहे बस्तर संभाग में कुल सात जिले शामिल हैं जिनमें बस्तर, कांकेर, कोंडागांव, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और बीजापुर हैं। सीआरपीएफ के जवानों को बड़ी संख्या में दक्षिण बस्तर क्षेत्र में तैनात किया गया है, जिसमें सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले शामिल हैं। यहां सीआरपीएफ के नेतृत्व में सुरक्षा कर्मियों ने कई बड़े माओवादी हमलों में जवाबी कार्रवाई की है।

गेवरा खदान में भू-विस्थापितों का प्रदर्शन, परिवहन को भी किया ठप

संगठन के साथ मिलकर ग्रामीणों ने बंद कराई खदान

कोरबा। कोरबा में 11 सुत्रीय मांगो को लेकर उर्जाधानी भू-विस्थापित कल्याण समिती ने एसईसीएल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सैकड़ों ग्रामीणों के साथ संगठन ने गेवरा खदान में उत्पादन के साथ ही परिवहन को ठप कर दिया। सुबह होते ही आंदोलनकारी खदान के भीतर घुस गए और उत्पादन में लगी मशीनों को बंद करा दिया। भू-विस्थापितों के इस आंदोलन से प्रबंधन को बड़ा नुकसान होने की बात कही जा रही है।

11 सूत्रीय मांगों को लेकर कोरबा की गेवरा खदान में ऊर्जाधानी विस्थापित संगठन ने एसईसीएल के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए खदान में उत्पादन और परिवहन को ठप कर दिया है। संगठन ने पहले ही इस आंदोलन की चेतावनी दी थी जिसके बाद प्रदर्शन किया जा रहा है। संगठन चाहता है कि भू-विस्थापितों को रोजगार दें, रेल कॉरिडोर से प्रभावित लोगों के मुआवजा संबंधी समस्याओं का जल्द निराकरण हो, श्रमिक पंजीयन, भू अर्जन का मुआवजा देने के साथ ही अन्य मांगों को जल्द से जल्द पूरा करें। सैंकड़ो की संख्या में भू विस्थापित खदान के भीतर पहुंच गए है और उत्खनन में लगे मशीनों को बंद करा दिया। उत्पादन ठप होने से प्रबंधन को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है।

ऊर्जाधानी भू-विस्थापित कल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष सपुरन कुलदीप ने बताया कि एसईसीएल के भू-विस्थापितों की समस्या पिछले लंबे समय से चल रही है जिसे लेकर कई बार आंदोलन प्रदर्शन और खदान भी बंद की गई। लेकिन, किसी तरह के प्रबंधन के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। आज समिति के निर्णय के बाद विस्थापितों के साथ सैकड़ों की संख्या में सुबह से ही खदान बंद कराने पहुंचे हैं जहां उत्पादन पूरी तरह से ठप है। विस्थापित सुबह से ही गेवरा खदान के मुख्य द्वार और खदान के अंदर काम बंद कर रहे हैं जिसमें काफी आक्रोश ग्रामीणों में देखा जा रहा है यह आंदोलन अनिश्चितकालीन है अगर उनके 11 सूत्री मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो वह खदान पर ही आंदोलन जारी रखेंगे वही आंदोलन की सूचना मिलते ही दीपका थाना पुलिस और सीआईएसएफ के जवान के अलावा एसईसीएल की सुरक्षा गार्ड काफी संख्या में तैनात है लेकिन ग्रामीणों के विरोध के सामने इनका कुछ नहीं चल रहा है फिलहाल आंदोलन जारी है।

गोवा घूमने वाले शिक्षकों पर गिरेजी गाज, मेडिकल लीव बनाने वाले बीएमओ पर भी संकट

तीन प्राचार्यों की टीम करेगी जांच

बालोद। बोर्ड परीक्षाओं के दौरान मेडिकल लीव लेकर गोवा भ्रमण करने वाले शिक्षकों के संदर्भ में खबर प्रकाशन के बाद बड़ा असर हुआ है। शिक्षा विभाग पूरी तरह मामले को लेकर एक्टिव हो गया है। वहीं, जिन विद्यालयों में यह शिक्षक अध्ययन कर आते हैं उन विद्यालयों के शाला प्रबंधन समिति भी अपने स्तर पर बैठक कर रिपोर्ट तलब करने की बात कह रही है। ग्राम ठेकवा के शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष नोहर साहू ने बताया कि जिस तरह की बातें सामने आ रही है वह बिल्कुल ही अनैतिक है और हम आज बैठक कर रहे हैं। पूरी रिपोर्ट शिक्षक के मुंह से सुनना चाहते हैं। वहीं, 3 सदस्यीय टीम टीम का गठन किया गया है। क्योंकि शिक्षक काफी लंबे समय से लोगों के रडार पर थे परंतु इनके कुछ पुख्ता मामले सामने नहीं आ पा रहे थे।

दो शिक्षक जो कि बोर्ड परीक्षाओं के दौरान मेडिकल लीव लगाकर गोवा भ्रमण करने गए थे। उन्होंने ही सोशल मीडिया में अपनी तस्वीरों को वायरल कर दिया था। जिसके बाद से मामला प्रकाश में है। मेडिकल रिपोर्ट बनाने वाले बीएमओ डॉक्टर घनराम रावटे पर भी कार्रवाई की तलवार लटक रही है। विकास खंड शिक्षा अधिकारी ललित चंद्राकर ने बताया कि सभी तरफ से इन

शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई के लिए बातें आ रही हैं। दोनों शिक्षकों ने शिक्षण व्यवस्था को पार्टटाइम और जमीन के काम को फुल टाइम बनाकर रखा था। सूत्रों के हवाले से यह खबर आई है कि यह एक स्थानीय व्यवसाई के शागिर्द के रूप में काम करते हैं। दोनों शिक्षकों के स्टाफ ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि स्कूल से आए दिन नदारद हो जाते थे।

तीन प्राचार्यों के टीम का गठन

विकास खंड शिक्षा अधिकारी ललित चंद्राकर ने बताया कि जिले पर जो आदेश मिले हैं। उसके अनुसार तीन प्राचार्यों की एक समिति का गठन किया गया है। जो कि, जांच रिपोर्ट तलब करेगी। उन्होंने बताया कि मामला चूंकि इतना गंभीर हो चला है इसके लिए यहां पर उनके आने जाने की टिकट सहित जहां पे रुके थे सभी चीजों की बारीकी से जांच किया जाएगा। जिसके बाद पूरे विषय में जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं, विकास खंड शिक्षा अधिकारी ने भी बताया कि सभी तरफ से इस मामले में कार्रवाई के लिए बातें सामने आ रही है।

बीएमओ भी जांच के दायरे में

गुरुर के विकास खंड चिकित्सा अधिकारी बीएमओ घनाराम रावटे जिन्होंने इन दो शिक्षकों का मेडिकल लीव जारी किया था। उसने मामले पर अपनी बातों को रखा है उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें जांच कराने के लिए कहा था। परंतु उन्होंने हॉस्पिटल में जांच नहीं कराई वहीं जब हमने स्कूल में मेडिकल रिपोर्ट जाकर देखा तो यह पता चला कि डॉ. बीएमओ घनाराम रावटे ने ही पहले अनफिट प्रमाण पत्र दिया। उसके बाद फिट प्रमाण पत्र भी दिया है। पूरे मामले में खबर प्रकाशन के बाद मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जेएल उइके ने मामले को संज्ञान में लिया है और उन्होंने भी बीएमओ के ऊपर जांच एवं कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जिस शागिर्द के नुमाइंदों के रूप में यह शिक्षक काम करते हैं। उनकी जमीन गुरुर नगर के सरस्वती शिशु मंदिर के आसपास प्लॉट कटिंग के लिए तैयार है। जिसमें इनके पार्टनरशिप हो सकती है। वहां मौरम बिछाकर प्लाटिंग की तैयारी हो चुकी है।

किसानों का फर्जी पंजीयन कर किया लाखों का गबन, दो आरोपी गिरफ्तार

जांजगीर चांपा। बलौदा थाना क्षेत्र के कोरबी धान खरीदी केंद्र में फर्जी पंजीयन कर चार लाख पांच हजार रुपये का गबन करने के मामले में तीन माह से फरार दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

बताया जा रहा है कि दिसंबर माह 2022 का यह पूरा मामला है। जहां कोरबी धान खरीदी केंद्र में फर्जी तरीके से किसानों का पंजीयन कराया गया और शासकीय राशि में लाखों रुपये की हेरा-फेरी की गई। जिसकी जांच के लिए जिला दंडाधिकारी से शिकायत की गई थी। फर्जी पंजीयन को लेकर गंभीरता से लेते हुए जांच टीम गठित की गई। जांच टीम के द्वारा जांच प्रतिवेदन के आधार पर मुकेश पांडे मैनेजर ग्रामीण सहकारी बैंक बलौदा के द्वारा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। जिसमें पूजा अग्रवाल एवं अन्य धान खरीदी केंद्र में किसानों का फर्जी पंजीयन कर फर्जीवाड़ा कर लाखों रुपये निकालकर गबन करने एवं धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया। जिसके बाद आरोपियों के विरुद्ध धारा 420, 409, 468,471,120 बी, 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।

थाना प्रभारी गोपाल साथपती ने बताया की किसानों का फर्जी पंजीयन कर कूट

रचना करते हुए धान खरीदी में शासकीय राशि चार लाख पांच हजार रुपये का गबन किया गया है। पूर्व में आरोपी मनोज अग्रवाल, सीमा अग्रवाल पति-पत्नी की संलिप्तता मिलने पर दोनों का नाम जोड़ा गया। जिसमें सीमा अग्रवाल और पूजा अग्रवाल को गिरफ्तार किया जा चुका है। जिसे माननीय छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बिलासपुर में प्रकरण के आरोपियों सीमा अग्रवाल और पूजा अग्रवाल को अग्रिम जमानत दिया है।

इस प्रकरण में दो आरोपी मनोज अग्रवाल, जितेंद्र अग्रवाल जोकि पिछले 3 माह से फरार चल रहे थे। पुलिस को सूचना मिली की दोनों आरोपी अपने घर आए हैं। जिसपर दोनों आरोपियों को घेराबंदी कर पकड़ा गया। दोनों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।

शीतला शक्ति पीठ सिहावा में आस्था के दीप जगमगा रहे

नगरी। चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ बुधवार से शुरू हो गया। नवरात्रि के प्रथम दिवस शीतला शक्ति पीठ सिहावा में ज्योति प्रज्वलित करने वालों की भीड़ लगी रही है । बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मां का

दर्शन कर अपनी मनोकामना के लिए आचार्य चन्द्रहास दुबे के सानिध्य में विधि विधान से पूजा अर्चना कर शुभ मुहूर्त में ज्योति प्रज्वलित की।इस वर्ष चैत्र नवरात्रि में 920 ज्योति जगमगा रहे है।जिसमें घी के 92 व तेल के 828ज्योति शामिल है शीतला शक्ति पीठ के अध्यक्ष कैलाश पवार ने बताया कि चैत्र नवरात्रि को उत्साह पूर्वक मनाने के लिये व्यापक तैयारी की गई है।रात्रि में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किये जा रहे है। तृतीय दिवस खेमीन यादव कृत जय गुरुदेव पंडवानी पार्टी खम्हरिया, चतुर्थ दिवस जय शम्भू बालिका रामधुनी झांकी घोटिया कांकेर, पंचमी को जय मरादेव मारिया झांकी पचपेड़ी, छठवे दिवस जय माँ विंध्यवासिनी महिला मानस रामधुनी मण्डली गोकुलपुर, सप्तम दिवस नव किरण रामधुनी गट्टाशिली, अष्टमी को खेमिन निषाद कृत पंडवानी गरियाबंद, नवमी को गुरु गीता मानस मण्डली अमली पारा की प्रस्तुति होगी। समिति के अध्यक्ष समिति के अध्यक्ष कैलाश पवार, संरक्षक कलम सिंह पवार,सचिव नेम सिंह बिशेन,नरेंद्र नाग, नारद निषाद, बुधेस्वर साहू, कोशाध्यक्ष रोंद लाल यादव, मंच संचालक तुकाराम साहू,गोरख शांडिल्य आदि व्यवस्था में जुटे हुए है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

अवैध रेत खनन पर जपं अध्यक्ष ने अधिकारियों पर उठाई उंगली

नगरी। नगरी क्षेत्र में हो रहे अवैध रेत खनन के मामले को शुक्रवार को आयोजित जिला पंचायत सामान्य सभा की बैठक में जनपद पंचायत नगरी की अध्यक्ष दिनेश्वरी नेताम ने उठाया। उन्होंने कहा कि महानदी, सीतानदी और बालका नदी में अवैध उत्खनन कर पर्यावरण के साथ-साथ शासन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। साथ ही प्रशासनिक अधिकारी और खनिज विभाग के अधिकारी मूकदर्शक बने हुए हैं। कार्यवाही के नाम पर ग्रामीणों को परेशान कर अवैध रसीद काटी जा रही है। जिला पंचायत में आज की सामान्य सभा की बैठक में जनपद अध्यक्ष दिनेश्वरी नेताम ने स्थानीय प्रशासन पर उंगली उठाते हुए कहा कि जो अवैध उत्खनन कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई न कर उनसे मिलीभगत कर अवैध वसूली की जा रही है। क्षेत्र के गरीब ग्रामीण जिनको छुटपुट रेत की जरूरत है उन्हें शिकार बनाकर उनके ट्रैक्टर चालानी कार्रवाई कर रहे हैं। रेत माफिया शासन प्रशासन के संरक्षण में मनमाने कीमत वसूल रहे हैं। शासन प्रशासन को चाहिए कि क्षेत्र में पेसा के तहत पंचायतों को पूर्ण अधिकार प्रदान किया जाए।

सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ध्वस्त

धमतरी। ग्राम पंचायत परेवाडीह में भाजपा समर्थित सरपंच खिलेश्वरी साहू के खिलाफ विपक्ष द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव गिर जाने के बाद गांव में बवाल मच गया जो देर रात तक जारी रहा। सूचना मिलने पर पुलिस तत्काल वहां पर पहुंची लेकिन ग्रामीणों और पुलिस के बीच भी जूतम पैचार हुआ। जिसके बाद अलसुबह मामला शांत हुआ और पुलिस ने पंचायत भवन से किसी तरह सरपंच, उसके पति और पंचों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाला। गांव में स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बताई गई है और पुलिस का पहरा जारी है। धमतरी ब्लॉक के परेवाडीह में जिला प्रशासन की ओर से छात्रों के हित में उद्यानिकी कॉलेज खोलने की घोषणा कर प्रारंभिक तैयारी शुरू की गई जिसके विरोध में गांव के एक वर्ग द्वारा विरोध किया जा रहा था। ग्राम विकास समिति को विश्वास में लिए बगैर कॉलेज के लिए पंचायत प्रस्ताव बनाने की बात को लेकर सरपंच के खिलाफ विरोध शुरू कर दिया। पिछले दिनों कलेक्ट्रेट का घेराव भी किया। इसके बाद पंचों ने सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का आवेदन दिया था।

ग्रामीणों के दर्द को समझने में प्रशासन नाकाम : महेन्द्र नेताम

नगरी। सीतानदी अभ्यारण्य क्षेत्र के निवासी वर्षो से सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। वनग्राम संघर्ष समिति के उपाध्यक्ष महेन्द्र नेताम ने दुखित होते हुए कहा कि इन समस्याओं से निजात पाने के लिए 34 ग्राम के ग्रामीणों ने समय - समय पर अपने हक के लिए धरना प्रदर्शन आंदोलन तक कर रहे हैं, पर अभ्यारण्य क्षेत्र के ग्रामीणों को कोई सुविधा नहीं मिल पाई है। इससे पहले तत्कालीन धमतरी कलेक्टर रजत बंसल(ढ्ढस्) स्वयं रिसगांव में ग्रामीणों के साथ जमीन पर बैठकर सभी समस्याओं पर गहन विमर्श किये थे। उस समय भी सभी मीठे मीठे विभाग भी मौजूद रहे। इसका कोई परिणाम नहीं दिखा। उसके बाद तत्कालीन कलेक्टर पी एस एल्मा, फिर अपर कलेक्टर तत्कालीन एसडीएम नगरी चंद्रकांत कौशिक और डीएफओ अभ्यारण्य, गरियाबंद से इन सभी मुद्दों पर चर्चा हुई है। सभी ने आश्वासन दिया कि शीघ्र व्यवस्था सुधरेगी, कार्य प्रारंभ हो जाएगा। दुर्भाग्य है, इन सभी से कनिष्ठ अधिकारी को चर्चा कराने भेजा गया।

उद्यमिता जागरूकता शिविर का आयोजन 27 मार्च को

कोरबा। स्वयं का उद्योग-व्यवसाय स्थापित करने के इच्छुक युवक-युवतियों को उद्योग स्थापना में सहायता करने एक दिवसीय उद्यमिता जागरूकता शिविर का आयोजन किया जाएगा। उद्यमियों को अनुदानित ऋण का लाभ देने के लिए शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था चोरभट्ठी गोपालपुर में 27 मार्च को शिविर का आयोजन किया जाएगा। यह शिविर दोपहर 12 बजे से आयोजित होगी। शिविर में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना एवं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत जिले के उद्यमी युवक - युवतियों को स्वयं का उद्योग-व्यवसाय स्थापना के लिए जागरूक और प्रोत्साहित किया जाएगा। महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र कोरबा ने बताया कि उद्यमिता जागरूकता शिविर में इच्छुक युवक-युवतियां, उद्यमी एवं स्वसहायता समूह के सदस्य निर्धारित तिथि एवं समय पर शिविर में उपस्थित होकर उद्योग-व्यवसाय स्थापना के बारे में जानकारी और लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

पूजा-पाठ के दौरान महिला आग की चपेट में आई

कोरबा। कोरबा में पूजा पाठ करने के दौरान एक महिला आग की चपेट में आने से सामान्य रुप से झुलस गई। सीएसईबी कॉलोनी में रहने वाली महिला जानकी साहू के साथ यह घटना घटी। महिला को पहले सीएसईबी के विभागीय अस्पताल में दाखिल किया गया जहां से उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। सामान्य रुप से जलने के कारण महिला की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के सीएसईबी कॉलोनी में रहने वाली एक वृद्ध महिला आग की चपेट में आने से सामान्य रुप से झुलस गई। हादसा होने के बाद महिला को तत्काल बुधवारी स्थिती सीएसईबी के विभागीय अस्पताल में भर्ती किया गया। जहां से उसे बेहतर उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। इस संबंध में सीएसईबी चौकी प्रभारी शिव कुमार धारी ने बताया कि सूचना मिलने के बाद महिला का बयान लेने पुलिस अस्पताल पहुंची। जहां उसने बताया कि नवरात्री की पूजापाठ करने के दौरान उसके साथ यह हादसा हुआ।

सिहावा क्षेत्र के 35 गाँवों को हर हाल मे मिले मूलभूत सुविधा : चुन्नीलाल

- **नियम 377 के अधीन सांसद चुन्नीलाल ने संसद में उठाया मामला**

नगरी। लोकसभा में 24 मार्च को छत्तीसगढ़ के महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के सांसद चुन्नीलाल साहू ने प्रदेश के धमतरी जिले के नगरी विकासखंड के 34-35 गाँवों के लगभग 12000 लोगों के आजादी के 75 वर्ष के बाद भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहते हुए जीवन यापन करने का मामला नियम 377 के अधीन, विभाजन संख्या 331 के अंतर्गत सदन मे उठाया। श्री साहू ने केंद्रीय वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री के समक्ष इस आशय की मांग करते हुए लिखा कि आजादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी छ्ग राज्य के नगरी विकासखंड के 34-35 गाँवों के लगभग 12000 लोग जिसमे 90त्न आदिवासी समाज से आते हैं, वे आज भी सड़क,

बिजली, पानी एवं दूरसंचार जैसी सुविधाओं से वंचित हैं। यहाँ उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व क्षेत्र होने के कारण जिला मुख्यालय से पक्की सड़क से सीधे संपर्क न होने के कारण उक्त सभी सुख सुविधाओं से यह क्षेत्र वंचित है। जबकि आजादी के पूर्व अंग्रेजी शासन काल में रेलवे के स्लीपर के परिवहन के लिये उक्त क्षेत्र में रेल लाइन बिछाई गयी थी। उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया कि गत वर्ष शासन द्वारा बिजली सुविधा देने की स्वीकृति मिली थी और टेंडर भी हो गये थे परंतु टाइगर रिजर्व क्षेत्र होने के कारण निर्माण कार्य की विभागीय अनुमति प्रदान नही की गयी। उक्त क्षेत्र केवल नाम का टाइगर रिजर्व क्षेत्र बन के रह गया है जबकि टाइगर वर्तमान मे देखने को भी नही मिलता। इस सुदूर क्षेत्र के निवासियों को सुविधाओं के अभाव मे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हे मूलभूत सुविधाएं मिले इसके लिये शीघ्रतिशीघ्र पहल कराये जाने की अति आवश्यकता है।

उन्होंने माननीय वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री से अनुरोध किया है कि क्षेत्र के निवासियों को बुनियादी सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, सड़क एवं दूरसंचार को संज्ञान मे लेते हुए विभागीय अनुमति प्रदान करें ताकि सुविधाओं से वंचित लोगों को उनके मौलिक अधिकार का लाभ मिल सके। गौरतलब है कि विगत दिनों हजारों की संख्या मे नगरी विकासखंड के उन 35-40 गाँवों के निवासी हजारों की संख्या मे 30-35 किमी पैदल मार्च करते हुए 5 घंटे से अधिक समय तक कलेक्ट्रेट का घेराव किया था। ऐसे मे सांसद द्वारा संसद मे उठाई गयी यह त्वरित मांग निश्चित रूप से उनकी संवेदनशीलता का परिचय है। क्षेत्र वासियों के द्वारा सांसद के इस महत्वपूर्ण प्रयासों के लिये उन्हे साधुवाद दिया जा रहा है।

भाजपा दफ्तर में घुसे युवा कांग्रेसी बैनर-पोस्टर भी फाड़े

कोरबा। जिला युवा कांग्रेस ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त करने के विरोध में शुक्रवार शाम रैली के साथ भाजपा कार्यालय टीपी नगर पहुंच गए। यहां पुलिस ने गेट पर रोकने का प्रयास किया तो युवा कांग्रेसियों ने झूमाझटकी की। कार्यालय परिसर पर लगे बैनर.पोस्टर को फाड़ दिया। इसके बाद पुलिस ने किसी तरह युवा कांग्रेसियों को बाहर निकाला। इधर भाजपा ने युवा कांग्रेसियों के खिलाफ थाने में शिकायत करने की बात कही है।

मानहानि के मामले में गुरुवार को सूरत के कोर्ट ने राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई है। इसके दूसरे दिन शुक्रवार को लोकसभा से उनके सदस्यता निरस्त करने की कार्रवाई की गई। इससे युवा कांग्रेसी भड़क गए। युवा कांग्रेस के महासचिव मधुसूदन दास और आशीष गुप्ता के नेतृत्व में टीपी नगर चौक से नारेबाजी करते हुए युवा कांग्रेसी भाजपा कार्यालय पहुंच गए। यहां टायर को जलाकर जमकर हंगामा किया। पुलिस ने गेट पर रोकने का प्रयास किया। इसके बाद भी झूमाझटकी करते हुए अंदर पहुंच गए थे। पुलिस ने किसी तरह काबू पाया। भाजपा जिलाध्यक्ष डॉ. राजीव सिंह ने कहा कि भाजपा कार्यालय में तोड़फोड़ करना निंदनीय है। इस मामले में एफआईआर करायी जाएगी। एडीशनल एसपी अभिषेक वर्मा ने बताया कि युवा कांग्रेसी भाजपा कार्यालय में घुस गए थे। किसी को चोट नहीं आई है।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

तेजस्वी यादव से सीबीआई ने की पूछताछ

नई दिल्ली। बिहार में नौकरी के बदले जमीन घोटाले मामले में बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से केंद्रीय जांच ब्यूरो ने पूछताछ की है। शनिवार को तेजस्वी यादव नई दिल्ली स्थिति सीबीआई दफ्तर पहुंचे जहां उन्होंने मामले से जुड़े कई सवालों का उन्होंने सामना किया। इस बीच डिप्टी सीएम ने कहा, हमने इसके खिलाफ लड़ने का फैसला किया है और हम जीतेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने हमेश एजेंसियों के साथ सहयोग किया है लेकिन देश में स्थिति ये हैं कि यह बहुत कठिन हो गया है। सीबीआई की तेजस्वी यादव से पूछताछ का ये घटनाक्रम दिल्ली उच्च न्यायालय के उस फैसले के कुछ दिनों बाद आया है। जब कोर्ट ने बिहार उपमुख्यमंत्री को ये आश्वासन दिया था कि इस महीने में उनकी गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। जिसके बाद ही तेजस्वी यादव 25 मार्च को सीबीआई दफ्तर में पेश होने के लिए सहमत हुए हैं।

सरकार ने नहीं, न्यायालय ने राहुल को दोषी ठहराया : हिमंत

गुवाहाटी। मानहानि मामले में सूरत कोर्ट से दोषी पाए जाने के बाद राहुल गांधी को 2 वर्षों की सजा सुनाई। इस सजा की वजह से राहुल गांधी को अपनी लोकसभा सदस्यता गवानी पड़ी है। इसको लेकर विपक्षी दल जबरदस्त तरीके से केंद्र सरकार पर हमलावर है। इन सबके बीच असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि कोर्ट ने ओबीसी समुदाय के पक्ष में फैसला सुनाया है। कभी-कभी संबोधन में गलत शब्द निकल जाते हैं, परन्तु मैं ऐसा होने पर माफी मांगता हूं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कोर्ट के आदेश के बाद भी माफी नहीं मांग रहे, ये उनका अहंकार है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि राहुल गांधी को भारत सरकार ने अयोग्य नहीं ठहराया है। उन्हें न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है क्योंकि उन्होंने अपने भाषण में ओबीसी समुदाय के खिलाफ असंसदीय, मानहानिकारक शब्दों का प्रयोग किया था और न्यायालय के फैसले के परिणामस्वरूप उन्हें अयोग्य घोषित किया गया है। यह एक न्यायिक प्रक्रिया है और इसमें कुछ भी राजनीतिक नहीं है।

राहुल गांधी के समर्थन में वायनाड में कांग्रेस का प्रदर्शन

तिरुवनंतपुरम। केरल के वायनाड के कुछ हिस्सों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लोकसभा सांसद के रूप में राहुल गांधी की अयोग्यता के विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के सुधाकरन ने घोषणा की कि पार्टी वायनाड में उपचुनाव के लिए तैयार है। यूथ कांग्रेस और केरल छात्र संघ के सदस्यों सहित पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने राजभवन तक मार्च निकाला। जब पुलिस ने मार्च को रोका और राजभवन की ओर जाने वाली सड़क पर बैरिकेड्स लगा दिए, तो कांग्रेस के लोगों ने विरोध करते हुए इसे पीछे खींचने की कोशिश की। लोकसभा से राहुल गांधी की अयोग्यता के विरोध में वायनाड जिला कांग्रेस कमेटी शनिवार को ब्लैक डे मनाई जिसकी जानकारी वायनाड जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एनडी अप्पाचन ने दी। कलपट्टा में टेलीफोन एक्सचेंज के कार्यालय तक कांग्रेस पार्टी द्वारा एक विरोध मार्च आयोजित किया गया था। इसके अलावा सुल्तान बाथेरी, मीनांगडी और मनंथवाडी में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध मार्च निकाला गया।

धर्मेंद्र प्रधान और अनुराग ठाकुर पर हमलावर हुए कपिल सिब्बल

नई दिल्ली। राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने शनिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर मोदी उपनाम संबंधी उनकी टिप्पणी को लेकर अन्य पिछड़ा वर्ग का अपमान करने का आरोप लगाने के लिए भाजपा के दो नेताओं धर्मेंद्र प्रधान और अनुराग ठाकुर पर शनिवार को निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये नेता इस तरह के बेतुके आरोप लगाकर लोगों की बुद्धिमत्ता का अपमान कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्रियों धर्मेंद्र प्रधान और अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को एक संवाददाता सम्मेलन में गांधी पर ओबीसी का अपमान करने का आरोप लगाया था, जिसपर सिब्बल ने प्रतिक्रिया दी और ट्वीट करते हुए लिखा, धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर : राहुल ने ओबीसी का अपमान किया। इस प्रकार के बेतुके आरोप लगाकर आप हमारी बुद्धिमत्ता का अपमान कर रहे हैं। सूरत की एक अदालत द्वारा मानहानि के एक मामले में सजा सुनाए जाने के मद्देनजर सांसद राहुल गांधी को शुक्रवार को लोकसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था।

कर्नाटक चुनाव : कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की पहली सूची

बेंगलुरु। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने शनिवार को अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। कांग्रेस ने 124 उम्मीदवारों के नाम इस लिस्ट में शामिल किए हैं, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे को भी टिकट मिला है। कांग्रेस ने मैसूर में वरुणा विधानसभा सीट के पूर्व सीएम सिद्धारमैया को मैदान में उतारने का फैसला किया है जो उनका गृह निर्वाचन क्षेत्र भी है। वहीं, केपीसीसी प्रमुख डीके शिवकुमार को कनकपुरा से मैदान में उतारने की तैयारी हैं। जानकारी के मुताबिक, सूची में शामिल अन्य नामों में यमकानमर्डी से कांग्रेस नेता सतीश जारकीहोली, चितापुर से प्रियांक खड़गे, बेलगाम ग्रामीण से लक्ष्मी हेब्बलकर, शिवाजीनगर से रिजवान अरशद, नरसिम्हाराजा से तनवीर सैत, गांधीनगर से दिनेश गुंडू राव, चामराजपेट से बीजेड जमीर अहमद खान शामिल हैं। कोराटागेरे से जी परमेश्वर और देवनहल्ली से पूर्व मंत्री केएच मुनियप्पा सहित अन्य उम्मीदवारों को पार्टी ने इस बार मौका दिया है।

कर्नाटक के चिकबल्लापुर में मेडिकल कॉलेज का प्रधानमंत्री ने किया उद्घाटन

भारत ने विकसित होने का लिया है संकल्प : मोदी

बेंगलुरु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिकबल्लापुर में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की मौजूदगी में मधुसूदन साईं इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान बोलते हुए पीएम ने कहा है कि देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या दोगुनी हो गई है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 70 हो गई है। देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 650 हो गई है। उन्होंने कहा कि भारत ने खुद को विकसित बनाने का फैसला कर लिया है। उन्होंने कहा कि देश सबकी भागीदारी से बढ़ रहा है। इस वर्ष चुनावी राज्य कर्नाटक में यह प्रधानमंत्री का सातवां दौरा है।

कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आजादी के अमृत महोत्सव में देश ने विकसित होने का संकल्प लिया है। कई बार लोग पूछते हैं कि भारत कैसे विकसित बनेगा? इतनी चुनौतियां हैं, इतना काम है, इतने कम समय में पूरा कैसे होगा? इस सवाल का जवाब है- सबका प्रयास। हर देशवासी के साझा प्रयासों से ये संभव होने वाला है।

पीएम ने कहा है कि बीते 9 वर्षों में भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बहुत ईमानदारी से और बहुत कुशलता से काम करने की कोशिश की है। देश में मेडिकल एजुकेशन से जुड़े कई सुधार किए गए हैं।पीएम ने अपनी कर्नाटक यात्रा के दौरान कहा कि चिकबल्लापुर आधुनिक भारत के आर्किटेक्ट में से एक सर एम. विश्वेश्वरय्या की जन्मभूमि है। इस पुण्य भूमि को मैं सिर झुका प्रणाम करता हूं।

इससे पहले बताया गया था कि पीएम मोदी चिक्कबल्लापुर में श्री मधुसूदन साईं इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च (एसएमएसआईएमएसआर) और बंगलूरू की कृष्णराजपुरा मेट्रो स्टेशन की व्हाइटफील्ड (कादुगोडी) लाइन के 13.71 किलोमीटर लंबे हिस्से के दूसरे चरण का उद्घाटन करेंगे और ट्रेन में यात्रा भी करेंगे। इस मेट्रो लाइन के निर्माण पर 4250 करोड़ रुपये की लागत आई है। पीएमओ ने एक बयान में कहा, इस मेट्रो लाइन का उद्घाटन बंगलूरू में यात्रियों को एक स्वच्छ, सुरक्षित, तेज और आरामदायक यात्रा सुविधा प्रदान करेगा और शहर में यातायात की भीड़ को कम करेगा।

छात्रों को मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च क्षेत्र में नए

अवसरों का लाभ उठाने और सुलभ और सस्ती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में मदद करने वाली एक पहल के तहत प्रधानमंत्री चिक्कबल्लापुर में श्री मधुसूदन साईं इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के अनुसार, संस्थान की स्थापना श्री सत्य साईं विश्वविद्यालय द्वारा मानव उत्कृष्टता के लिए सत्य साई ग्राम, मुदेनहल्ली, चिक्कबल्लापुर में की गई है।

एक ग्रामीण क्षेत्र में स्थित और चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा को गैर-व्यावसायिक बनाने की दृष्टि से स्थापित, एसएमएसआईएमएसआर मुफ्त में चिकित्सा शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा देखभाल प्रदान करेगा। संस्थान शैक्षणिक वर्ष 2023 से काम करना शुरू कर देगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आरोग्य के साथ-साथ माताओं, बहनों, बेटियों के आर्थिक सशक्तिकरण पर भी डबल इंजन सरकार का पूरा ध्यान है। उन्होंने कहा कि जैसा कि सामूहिक प्रयास भारत के विकास की दिशा में चमत्कारिक परिणाम ला सकते हैं, भाजपा जन भागीदारी पर ध्यान केंद्रित कर रही है। भारत की विकास यात्रा में सामाजिक और धार्मिक संगठनों की बड़ी भूमिका है। विशेष रूप से, कर्नाटक ऋषियों, आश्रमों, मठों की समृद्ध भूमि रही है। ये प्राचीन परंपराएं यहां बहुत जीवंत हैं।

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर में भाजपा का विजय डंका : मोदी

कर्नाटक में पीएम मोदी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि हर बार देखा है कि आपका आशीर्वाद बढ़ता जाता है। मैं कर्नाटक भाजपा का धन्यवाद करना चाहता हूं जिनके प्रयास से मैं यहां आया। ये विजय संकल्प रैली नहीं नजर आ रहा है। ये तो विजय रैली की तरह ही है। पीएम मोदी ने विजय संकल्प यात्रा महा संगम को संबोधित करते हुए कहा कि कर्नाटक ने राज्य में डबल इंजन सरकार को वापस लाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह नतीजा साफ दिखा रहा है कि डबल इंजन सरकार की धमाकेदार वापसी का निर्धार कर्नाटक ने कर लिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर में भाजपा का विजय डंका बज गया। ये एक प्रकार से विजय संकल्प रैली का शुभ संकेत है कि विजय यात्रा आरंभ हो चुकी है। पीएम मोदी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि आज सुखद संयोग है, आज विजय संकल्प रैली हो रही है और उसी समय कलबुर्गी, कर्नाटक में...जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कर्मभूमि है मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव था और कलबुर्गी में भारतीय जनता पार्टी के मेयर और डिप्टी मेयर जीत गये। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर में भाजपा का विजय डंका बज गया। यह एक प्रकार से विजय संकल्प रैली का शुभ संकेत है कि विजय यात्रा आरंभ हो चुकी है। आगे पीएम मोदी ने कहा कि सोशल मीडिया पर कल मैंने कर्नाटक का एक वीडियो देखा। एक पार्टी के बड़े नेता...कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री, अपनी ही पार्टी के एक कार्यकर्ता को सार्वजनिक रूप से थप्पड़ मारने का आनंद ले रहे थे। जो अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं कर सकते, वो जनता जनार्दन का सम्मान क्या करेंगे? पीएम मोदी ने कहा कि कर्नाटक भाजपा का हर कार्यकर्ता, मेरे लिए मेरा एक मजबूत साथी है। यहां का हर कार्यकर्ता मेरा परम मित्र है, मेरा सहोदर है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक ने अवसरवादी और स्वार्थी गठबंधन की सरकारों का लंबा दौर देखा है। ऐसी सरकारों से कर्नाटक को हमेशा नुकसान हुआ है। इसलिए कर्नाटक के तेज विकास के लिए भाजपा की पूर्ण बहुमत की स्थिर सरकार बहुत जरूरी है।

सदस्यता गंवाने के बाद बोले राहुल गांधी

मेरा नाम सावरकर नहीं, गांधी किसी से माफी नहीं मांगता

नई दिल्ली। मोदी सरनेम मानहानि मामले में संसद सदस्यता गंवा चुके कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार कहा कि अयोग्य ठहराने, मंत्रियों द्वारा आरोप लगाने का पूरा खेल अडानी मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए खेला गया। कांग्रेस के पूर्व सांसद ने कहा कि मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता।

राहुल गांधी ने लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने के बाद पहले संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मंत्रियों ने मेरे बारे में झूठ बोला कि मैंने विदेशी हस्तक्षेप के लिए कहा था, मैंने ऐसा नहीं कहा। कांग्रेस नेता ने कहा- मैं अडानी मुद्दे पर सवाल पूछता रहूंगा, वे अयोग्य ठहराकर या मुझे जेल में रखकर मुझे डरा नहीं सकते। मैं झुकूंगा नहीं।

राहुल गांधी ने एक बार फिर कहा कि मैं यहां भारत के लोगों की लोकतांत्रिक आवाज की रक्षा करने के लिए हूं। ऐसा करता रहूंगा, मैं किसी से नहीं डरता। बकौल राहुल गांधी- मुझे फर्क नहीं पड़ता की मैं संसद के अंदर हूं या बाहर हूं। मुझे अपनी तपस्या करनी है, मैं उसे करके दिखाऊंगा।

राहुल गांधी ने आगे कहा- भारत जोड़ो यात्रा की मेरी कोई भी स्पीच देख लीजिए, मैंने हमेशा कहा है कि सब समाज एक हैं। नफरत, हिंसा नहीं होनी चाहिए।

ये ओबीसी का मामला नहीं है, ये नरेंद्र मोदी और अडानी के रिश्ते का मामला है। भाजपा ध्यान को भटकाने का काम करती है, कभी ओबीसी की बात करेगी, कभी विदेश की बात करेगी।

कांग्रेस नेता ने फिर दोहराया कि मैं सवाल पूछना बंद नहीं करूंगा। अडानी का नरेंद्र मोदी से क्या रिश्ता है? इन लोगों से मुझे डर नहीं लगता। अगर इनको लगता है कि मेरी सदस्यता रद्द करके, डराकर, धमकाकर, जेल भेजकर मुझे बंद कर सकते हैं। मैं हिन्दुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और लड़ता रहूंगा।

अडानी सेवक ने जनसेवक की आवाज दबाने की रची साजिश : प्रियंका गांधी

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने पर बोलते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट कर एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें संसद में राहुल गांधी पीएम मोदी और अडानी को लेकर बोल रहे है। ऐसे में वीडियो को ट्वीट करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा है कि अडानी को लेकर सवाल पूछे जाने पर जनसेवक की आवाज दबाने की कोशिश की गई है। ऐसे में उनका कहना है कि इस मामले में जवाब देना होगा। यही नहीं राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने पर कई और नेताओं ने अपनी नाराजगी जाहिर की है और इस पर बोला है। ऐसे में इस मुद्दे पर बोलते हुए प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी के उस ट्वीट को रि-ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं भारत की आवाज़ के लिए लड़ रहा हूं। मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं। रि-ट्वीट करते हुए प्रियंका ने कहा है कि इन्हीं सवालों के लिए राहुल गांधी पर हमला किया जा रहा है। जनता द्वारा चुने हुए जनसेवक ने जनता की तरफ से सवाल पूछे तो अडानी-सेवक ने जनसेवक की आवाज दबाने की साजिशें रच डालीं...लेकिन जनता की आवाज दबाई नहीं जा सकती। ये सवाल अब देश भर में गूंजेंगे और जवाब देना होगा।

खेल
प्रमुख समाचार

सात्विक-विराग की जोड़ी स्विस ओपन के सेमीफाइनल में पहुंची

बासेल। सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय पुरुष युगल जोड़ी ने तीन गेम तक चले कड़े मुकाबले में डेनमार्क के जेपी बे और लासे मोल्हेडे को हराकर स्विस ओपन सुपर सीरीज 300 बैडमिंटन प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। भारतीय जोड़ी ने शुक्रवार की रात को खेले गए मुकाबले में 54 मिनट में 15-21, 21-11, 21-14 से जीत दर्ज की। सात्विक और चिराग का अगला मुकाबला ओंग यू सिन और टियो ई यी की मलेशियाई जोड़ी से होगा।

पीवी सिंधू और लक्ष्य सेन जैसे खिलाड़ियों के शुरू में ही बाहर हो जाने के बाद अब भारत का दारोमदार पुरुष युगल की इस स्टार जोड़ी पर ही टिका है। भारतीय जोड़ी की शुरुआत अच्छी नहीं रही। पहले गेम में एक समय वह केवल 15-16 के स्कोर पर एक अंक से पिछड़ रही थी लेकिन इसके बाद डेनमार्क की जोड़ी ने लगातार छह अंक बनाकर पहला गेम अपने नाम किया। सात्विक और चिराग ने दूसरे गेम में लय हासिल की और इंटरवल तक 11-4 की मजबूत बढ़त बना दी।

इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और दूसरा गेम जीतकर मैच को निर्णायक गेम तक पहुंचा दिया। तीसरे गेम में भी भारतीय जोड़ी ने अच्छा प्रदर्शन किया और इंटरवल तक वह 11-7 से आगे थी। इसके बाद उसने सात अंक की बढ़त बनाई और उसे आखिर तक बरकरार रखकर शान से सेमीफाइनल में जगह बनाई। भारतीय जोड़ी ने इस टूर्नामेंट में अच्छी वापसी की है क्योंकि इससे पहले ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप में उसे पहले दौर में ही बाहर होना पड़ा था।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

एवलॉन टेक्नोलॉजीज का आईपीओ 3 अप्रैल को खुलेगा

नई दिल्ली। इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण सेवाएं देने वाली कंपनी एवलॉन टेक्नोलॉजीज का 865 करोड़ रुपये का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) तीन अप्रैल को खुलेगा।कंपनी के आईपीओ संबंधी प्रारंभिक दस्तावेज के मुताबिक, उसका तीन-दिवसीय सार्वजनिक निर्गम छह अप्रैल को बंद होगा। एंकर निवेशक 31 मार्च को बोली लगा सकेंगे। पहले कंपनी का 1,025 करोड़ रुपये का आईपीओ लाने का प्रस्ताव था लेकिन बाद में इसका आकार घटाकर 865 करोड़ रुपये कर दिया गया है। सार्वजनिक निर्गम के तहत कंपनी 320 करोड़ रुपये नए शेयर जारी कर जुटाएगी जबकि प्रवर्तकों एवं मौजूदा शेयरधारकों के पास मौजूद शेयरों की खुली बिक्री से 545 करोड़ रुपये जुटाने की योजना है। वर्ष 1999 में स्थापित एवलॉन अन्य कंपनियों को इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण सेवाएं देने का काम करती है। अमेरिका और भारत में इसके 12 विनिर्माण संयंत्र हैं।

किफायती घरों की आपूर्ति में गिरावट का दौर जारी

नई दिल्ली। देश के सात प्रमुख शहरों में 40 लाख रुपये से कम कीमत वाले किफायती घरों की कुल नए घरों में हिस्सेदारी घटकर पिछले साल 20 प्रतिशत पर आ गई। रियल एस्टेट सलाहकार फर्म एनरॉक ने यह जानकारी दी है। एनरॉक ने किफायती घरों की संख्या में आई इस गिरावट के लिए महंगी जमीन, कम लाभ और कम ब्याज दरों पर वित्त नहीं मिलने जैसे कारकों को जिम्मेदार ठहराया है। आंकड़ों के अनुसार, रियल एस्टेट डेवलपर ने वर्ष 2022 में देश के सात प्रमुख शहरों में कुल 3,57,650 घरों की आपूर्ति की जिनमें से सिर्फ 20 प्रतिशत घर ही किफायती श्रेणी में थे। इसके पहले साल 2018 में कुल 1,95,300 घर तैयार किए गए थे, जिनमें से 40 प्रतिशत घर किफायती श्रेणी के थे। वर्ष 2019 में बने कुल 2,36,560 घरों में से किफायती घरों का हिस्सा 40 प्रतिशत पर स्थिर रहा।

जियो ने 5जी नेटवर्क के लिए देश भर में 1 लाख टावर लगाए

नई दिल्ली। देश की अग्रणी दूरसंचार कंपनी रिलायंस जियो ने अत्यधिक तीव्र गति वाली इंटरनेट सेवा देने के लिए सबसे तेज और व्यापक 5जी दूरसंचार नेटवर्क खड़ा करने के मकसद से देश भर में करीब एक लाख दूरसंचार टावर लगाए हैं। दूरसंचार विभाग के हालिया आंकड़ों के अनुसार, दूरसंचार टावर लगाने के मामले में जियो दूसरे स्थान पर मौजूद कंपनी से लगभग पांच गुना आगे है। दूरसंचार विभाग के नेशनल ईएमएफ पोर्टल पर जारी दैनिक स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, जियो ने 700 मेगा हर्ट्ज और 3,500 मेगा हर्ट्ज वाले 99,897 बीटीएस (बेस ट्रांसीवर स्टेशन) स्थापित किए हैं। वहीं दूसरे स्थान पर मौजूद कंपनी भारती एयरटेल ने कुल 22,219 बीटीएस स्थापित किए हैं। बृहस्पतिवार को मौजूद स्थिति के अनुसार, प्रत्येक आधार स्टेशन के लिए जियो के पास तीन सेल इकाइयां हैं जबकि एयरटेल के पास दो सेल इकाइयां हैं।

पूर्व तटीय रेलवे ने 23.23 करोड़ टन माल की ढुलाई की

नई दिल्ली। पूर्व तटीय रेलवे (ईकोर) खंड ने चालू वित्त वर्ष (2022-23) में अभी तक 23.23 करोड़ टन माल की ढुलाई कर नया रिकॉर्ड बनाया है। रेलवे के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि ईकोर ने वित्त वर्ष 2021-22 में समान अवधि के दौरान 22.36 करोड़ टन माल का परिवहन किया था और संपूर्ण वित्त वर्ष में कुल माल ढुलाई 23.32 करोड़ टन की थी। पूर्व तटीय रेलवे एकमात्र रेलवे खंड है जो 22 करोड़ टन और 23 करोड़ टन का आंकड़ा पार करने के बाद चालू वर्ष में 24 करोड़ टन माल परिवहन के आंकड़े की ओर बढ़ रहा है। रेल मंत्रालय ने पूर्व तटीय रेलवे के लिए चालू वित्त वर्ष में माल परिवहन का लक्ष्य 24.06 करोड़ टन तय किया है।

वैश्विक संकट में भी मजबूत है भारत का अर्थतंत्र

डॉ. जयंती लाल भण्डारी

हाल ही में 18 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक महत्वपूर्ण कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए कहा कि आज वैश्विक आर्थिक संकट के बीच भी भारत का अर्थतंत्र मजबूत है। दुनिया में भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था का चमकता हुआ देश बताया जा रहा है। इस समय भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। जहां भारत में प्रत्यक्ष विदेशी-निवेश (एफडीआई) बढ़ रहे हैं, वहीं भारत से निर्यात भी बढ़ रहे हैं। भारत वैश्विक सप्लाई चेन का अहम हिस्सा बन रहा है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम (पीएलआई) से देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और आत्मनिर्भर भारत अभियान आगे बढ़ रहा है।

इन दिनों पूरी दुनिया में दो ख्याति प्राप्त वैश्विक संगठनों के द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में हाल ही में प्रकाशित रिपोर्टों को गंभीरतापूर्वक पढ़ा जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की बढ़ी हुई अनिश्चितताओं के बीच भारत का मजबूत आर्थिक प्रदर्शन दुनिया में भारत की अहमियत बढ़ा रहा है। वर्ष 2023 में कुल वैश्विक विकास में भारत 15 फीसदी से भी अधिक का योगदान देगा। जहां चालू वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की विकास दर दुनिया में सबसे अधिक करीब 6.8 फीसदी होगी, वहीं आगामी वित्त वर्ष 2023-24 में भी भारत की विकास दर 6.1 फीसदी के साथ फिर दुनिया में सर्वोच्च होगी।

वहीं संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक सामयिक मामलों के विभाग द्वारा प्रस्तुत 'विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2023' रिपोर्ट में भारत को उद्योग-कारोबार और निवेश के मद्देनजर विश्व का प्रमुख व आकर्षक स्थल बताया गया है।

यह कोई छोटी बात नहीं है कि 15 मार्च को वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022-23 के पहले 11 महीनों में वस्तु निर्यात 400 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है। वैश्विक निर्यात चुनौतियों के बीच भारत से निर्यात भी बढ़ रहे हैं। वर्ष 2021-22 में उत्पाद एवं सेवा निर्यात का जो मूल्य करीब 676 अरब डॉलर था, वह चालू वित्त वर्ष 2022-23 में बढ़कर 770 अरब डॉलर से भी अधिक हो सकता है।

एक ओर जहां प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के लिए भारत को चमकता स्थान माना जा रहा है, वहीं दुनिया के देश भारत से दवाई और कृषि सहित विभिन्न उत्पादों और सेवाओं के निर्यात बढ़ाने की पहल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले 8 वर्षों में 160 से अधिक देशों की कंपनियों ने भारत में अर्थव्यवस्था के 61 क्षेत्रों में निवेश किया है। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत को रिकॉर्ड 84 अरब डॉलर का विदेशी निवेश मिला था। इससे भारत को कई मोर्चों पर लाभ मिलेगा। भारत की अर्थव्यवस्था चीन की अर्थव्यवस्था की तुलना में लगातार तेज गति से आगे बढ़ रही है। आईएमएफ के मुताबिक इस वित्त वर्ष 2022-23 में चीन की अर्थव्यवस्था में करीब 3.3 फीसदी वृद्धि होने का अनुमान है और आगामी वित्त वर्ष 2023-24 में चीन की वृद्धि दर 4.4 फीसदी रह सकती है। दो वर्षों की चीन की ये वृद्धि भारत की वृद्धि दर से बहुत कम है। वस्तुत: भारतीय अर्थव्यवस्था चीन से होड़ करने में इसलिए भी सफल होते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि जहां कई उभरते हुए वैश्विक आर्थिक परिदृश्य भारत के हित में हैं, वहीं चीन के सामने कई आर्थिक मुश्किलें हैं। इस समय चीन में युवा कामगारों का अभाव है, अचल संपत्ति गिरावट के दौर में है। चीन में विनिर्माण और वित्त की समस्या है। चीन के प्रति वैश्विक नकारात्मकता और अमेरिका के साथ चीन के व्यापार संबंधों में कड़वाहट का भी उसकी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है। हम उम्मीद करें कि भारत के द्वारा इस वर्ष 2023 में जी-20 की अध्यक्षता के बीच ऐसे रणनीतिक प्रयत्न बढ़ाए जाएंगे, जिनसे चीन प्लस वन की जरूरत के मद्देनजर भारत के दुनिया के नए आपूर्ति केंद्र, मैन्युफैक्चरिंग हब, अधिक निर्यात, अधिक विदेशी निवेश और अधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने की डगर पर तेजी से आगे बढ़ने की संभावनाएं मुट्ठियों में ली जा सकेंगी।

दक्षिण में भाजपा को मेहनत की जरूरत

आर राजागोपालन

दक्षिणी राज्यों, विशेषकर तमिलनाडु, में उत्तर-दक्षिण का विभाजन गहरा है। दक्षिण के छह राज्यों की राजनीति पर आठ बड़ी जातियों का वर्चस्व है- वोक्कालिगा, लिंगायत, रेड्डी, कम्मा, गौड़ा, थेवर, नाडार और एझवा। दक्षिण भारत की राजनीति को समझने से पहले समाज में इन जातियों के वर्चस्व को समझना जरूरी है। उत्तर भारत में सोशल इंजीनियरिंग कारगर रही है, पर दक्षिण में यह अमित शाह जैसी चाणक्य राजनीति के लिए बड़ा अवरोध है। ऑस्कर जीतने वाला गाना नाटु नाटु भी एक सामाजिक ताना-बाना है। निश्चित रूप से यह विभिन्न क्षेत्रों को एकताबद्ध करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उदारतापूर्वक एक तेलुगू विद्वान को राज्यसभा में नामित किया है तथा पद्म सम्मानों का 35-40 प्रतिशत हिस्सा दक्षिण के लोगों को मिलता है। प्रधानमंत्री के %मन की बात% के सौ भागों में 65 बार दक्षिणी राज्यों का उल्लेख हुआ है। उत्तर भारत दक्षिण को गले लगाना चाहता है, पर क्या दक्षिण भारतीय इसे स्वीकार करेंगे? त्रिपुरा और मेघालय जैसे पूर्वोत्तर के राज्यों को जीतने में मोदी रणनीति कामयाब रही है, पर मोदी का जादू दक्षिण में केवल कर्नाटक और पुडुचेरी में ही चल पाया है। इसके विस्तार के लिए वे वाराणसी और सौराष्ट्र में तमिल संगमम का आयोजन कर रहे हैं।

बिहार के प्रवासियों का मुद्दा बहुत गर्म है और संवेदनशील भी है। एक चिंगारी एकता को अस्थिर कर सकती है। मार्च के प्रारंभ में बिहार और झारखंड के प्रवासियों के मसले को पर्दे के पीछे से गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मिलकर प्रभावी ढंग से संभाल लिया। इसमें सक्षम अधिकारियों ने उल्लेखनीय योगदान दिया। इसी प्रकार, हिंदू धर्म से ईसाई और इस्लाम धर्म में धर्मांतरण भी बेहद संवेदनशील मसला है, जो दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में चुपचाप चल रहा है। इस बारे में तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि ने एक रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी है। दक्षिण, विशेषकर तमिलनाडु एवं केरल, में तीसरा खतरनाक मामला पीएफआई और एसडीपीआई जैसे संगठनों की गतिविधियां हैं। दोनों राज्यों में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के छापों से इन पर लगाम लगी है। आंध्र प्रदेश में बड़े पैमाने पर हो रहे धर्मांतरण पर भी विचार किया जाना चाहिए। लेकिन राज्य में सत्तारूढ़ मुख्यमंत्री जगन रेड्डी राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के बहुत निकट हैं। आंध्र प्रदेश में मुख्य विपक्षी पार्टी तेलुगू देशम है। इसके नेता नारा चंद्रबाबू नायडू राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में शामिल होने के लिए बेचैन हैं तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कांग्रेस दूर-दूर तक नहीं है। उसने इन तेलुगू भाषी राज्यों का बंटवारा कर अपनी ही कब्र खोद ली। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बात करें, तो तेलंगाना में भी राजनीतिक स्तर पर उथल-पुथल की स्थिति है। लेकिन चंद्रशेखर राव ने राज्य को नेतृत्व प्रदान किया है। दक्षिणी राज्यों में सक्रिय शराब लॉबी ने राव की पार्टी तेलंगाना राज्य समिति (टीआरएस) की छवि धूमिल कर दी है। अब उन्होंने इस पार्टी का नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) कर दिया है। इस पार्टी का आम आदमी पार्टी से जुड़ाव बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया तथा टीआरएस नेता कविता का शराब घोटाले में नाम आने से इन दोनों युवा राजनेताओं का राजनीतिक भविष्य खराब हुआ है। कविता एक देशतर्रर मह्लिा राजनेता हैं। पर अतीत यह बताता है कि दक्षिण भारत के नेताओं के परिजनों ने अपने पिताओं और उनकी पार्टियों की छवि को धूमिल किया है। चंद्रशेखर राव इसके ज्वलंत उदाहरण हैं।

एक सांसद की निरर्हता

ऐश्वर्य पुरोहित

गत 23 मार्च को सूरत की एक अदालत ने मानहानि के एक मामले में वायनाड संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के सदस्य राहुल गांधी को दोषी पाते हुए उन्हें दो साल की सजा सुनायी है। तदुपरान्त 24 मार्च 2023 को लोकसभा सचिवालय की एक अधिसूचना द्वारा उन्हें लोकसभा की सदस्यता के अयोग्य घोषित कर दिया और तरह लोकसभा में उनकी सीट रिक्त हो गई।

इसके बाद से ही देशभर में संवैधानिकता और असंवैधानिकता पर बड़ी-बड़ी बातें शुरु हो गईं। कहीं-कहीं तो बात इतनी बिगड़ी कि कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई और पथराव तक हो गया। एक ओर कांग्रेसियों का कहना है कि सरकार ने राहुल गांधी की आवाज को दबाने के लिए ऐसा किया है, वहीं दूसरी ओर भाजपाइयों का कहना है कि यह उनके (राहुल गांधी के) कर्मों का ही फल है। इन दोनों के अलावा एक तीसरा पक्ष भी है जो यह कहता दिख रहा है कि मानाकि राहुल गांधी दोषी पाए गए हैं लेकिन सरकार ने उन्हें अयोग्य घोषित करने में थोड़ी हड़बड़ी कर दी।

ऐसे में ये सवाल उठते हैं कि क्या वास्तव में लोकतंत्र की हत्या हुई है या फिर राहुल गांधी को उनके कर्मों की सजा मिली है या फिर सरकार ने उन्हें अयोग्य घोषित करने में क्या सही में थोड़ी आतुरता दिखा दी? इन प्रश्नों का सटीक उत्तर पाना कठिन नहीं है और न ही इसके लिए सूरत अदालत के पूरे निर्णय पर गौर करने की आवश्यकता है। अभी हमारे लिए केवल यह जानना आवश्यक है कि अदालत ने उन्हें भारतीय दण्ड संहिता की धारा 504 के तहत दोषी पाया है और उन्हें 2 साल की सजा सुनाई है। राहुल गांधी के पास अदालत के फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देने का विकल्प भी अभी खुला हुआ है।

पर अदालत के इस फैसले में संवैधानिकता या असंवैधानिकता का यदि कोई प्रश्न होगा भी तो ऊपरी अदालत ही उस पर निर्णय कर सकती है। अतएव यहाँ मूल विवाद उन्हें (राहुल गांधी को) लोकसभा की सदस्यता से वंचित किये जाने का है। तो इसे समझने के लिए हमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 101, 102, 190 व 191 पर गौर करना होगा जो संसद सदस्यों की अयोग्यता और इसकारण से सदन में उनके स्थान रिक्त करने हेतु प्रावधान करते है। संविधान के अनुच्छेद 101 के खण्ड (3) के उपखण्ड (क) के अनुसार यदि संसद के किसी सदस्य को अनुच्छेद 102(1) व 102(2) के अधीन अयोग्य घोषित कर दिया जाता है तो उसका स्थान रिक्त हो जाएगा, वहीं संविधान के अनुच्छेद 102 के खण्ड(1) के उपखण्ड(ङ) के अनुसार, कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए और उसका सदस्य बने रहने के लिए निरर्ह होगा यदि वह संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निरर्हित कर दिया हो। (A person shall be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament if he is so disqualified by or under any law made by parliament.)"

यह प्रावधान भारत की संसद को ऐसा कोई कानून बनाने की शक्ति देता है, जो संसद सदस्यों के लिए अनुच्छेद 102 के खण्ड (1) के उपखण्डों (क) से (घ) तक वर्णित अयोग्यताओं के अतिरक्त भी अन्य अयोग्यताएँ प्रवर्तित कर सकता हो। संविधान प्रदत्त इसी शक्ति का उपयोग करते हुए भारत की संसद ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 मे कतिपय अपराधों के लिए दोषसिद्धि पर अयोग्यता के अन्तर्गत ऐसे प्रावधान किए हैं जिससे यदि कोई व्यक्ति किसी न्यायालय द्वारा धारा 8 की उपधारा (1) एवं (2) से भिन्न किसी मामले में दोषी पाया जाता है और उसे दो साल से अन्यून (अर्थात् दो साल या उससे अधिक अवधि की) सजा मिलती है तो वह सदन का सदस्य चुने जाने या उस सदन का सदस्य बने रहने के योग्य नहीं रह जाता। इसी धारा में आगे अयोग्यता की अवधि भी बतायी गयी है जिसके अनुसार, ट्रकोई व्यक्ति जो [उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी अपराध से भिन्न] किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है और दो वर्ष से अन्यून के कारावास से दंडादिष्ट किया गया है, ऐसी दोषसिद्धि की तारीख से निरर्हित होगा और उसे छोड़े जाने से छह वर्ष की अतिरिक्त कालावधि के लिए निरर्हित बना रहेगा। (A person convicted of any offence and sentenced to imprisonment for not less than two years [other than any offence referred to in sub-section (v) or sub-section (w)] shall be disqualified from the date of such conviction and shall continue to be disqualified for a further period of si& years since his release.])_

अब चूँकि न्यायालय ने राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई है तो इसलिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 की उपधारा (3) के चलते वे सदन के सदस्य बने रहने के लिए अयोग्य हो गए हैं, अत: लोकसभा में उनका स्थान रिक्त हो गया और अब अगले आठ साल तक वे कोई चुनाव भी नहीं लड़ सकेंगे। लेकिन अब भी मुख्य प्रश्न तो रह ही गया है, जो विवाद की मूल जड़ है और वह यह कि आखिर सरकार को उन्हें अयोग्य घोषित करने की इतनी हड़बड़ी क्या थी जबकि अभी ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाया जा सकता है?

यह बात थोड़ी तार्किक भी लगती है। लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम की जिस धारा 8 का उल्लेख ऊपर किया गया है, उसकी उपधारा 4 भी कुछ ऐसा ही प्रावधान करती है। इस उपधारा के अनुसार जबतक दोषसिद्धि को तीन मास न बीत गए हों तब तक यह अयोग्यता प्रभवशील नहीं होगी और यदि इस बीच ऊपरी अदालत में अपील कर दी जाए तो जबतक उस अपील का निपटारा नहीं हो जाता तबतक उपर्युक्त कोई भी अयोग्यता लागू नहीं होगी। अत: एकबारगी तो यह लगता है कि सरकार का यह कृत्य निश्चित ही गैर-कानूनी है।

लेकिन जरा ठहरिए, वास्तव में यह प्रवाधान ही राजनेताओं का रक्षाकवच था, इसी का इस्तेमाल करते हुए कई राजनेता दोषसिद्धि के बावजूद कानून के कर्ता-धर्ता बने बैठे रहते थे। लेकिन 10 जुलाई 2013 को ट्र*लिली थॉमस वि. भारत संघ एवं अन्य [2013] 10 स्श्ष्ट 1130 प्रकरण*ट्ठ में एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 की इस उपधारा 4 को संविधान के अनुच्छेद 102 (1) व अनुच्छेद 191 (1) की उल्लंघनकारी धारा बताया और इसे अभिखण्डित कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने यह पाया कि, जैसे ही कोई व्यक्ति, जो संसद के किसी सदन या फिर किसी राज्य विधान मण्डल के किसी सदन का सदस्य था, संविधान के अनुच्छेद 102(1)(ङ) व 191(1)(ङ) के द्वारा या इनके अधीन किसी विधि द्वारा अयोग्य हो जाता है, तो सदन में उसका स्थान उसका संविधान के अनुच्छेद 101(3)(क) व 190(3)(क) के प्रभाव से स्वत: ही रिक्त हो जाता है तथा संसद लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 की उपधारा (4) की तरह ऐसा कोई प्रावधान नहीं कर सकती जो वह तिथि बताता हो कि किसी सदस्य की अयोग्यता कब लागू होगी और इस तरह उसकी जगह को संविधान के अनुच्छेद 102(1)(ङ) व 191(1)(ङ) के अधीन निरर्हता के कारण रिक्त होने से बचाता हो। (once a person who was a member of either House of Parliament or House of the State Legislature becomes disqualified by or under any law made by Parliament under Articles 102(v)(e) and 191(v)(e) of the Constitution, his seat automatically falls vacant by virtue of Articles 101 (3)(a) and 190(3)(a) of the Constitution and Parliament cannot make a provision as in sub-section (y) of Section } of the Act to defer the date on which the disqualification of a sitting member will have effect and prevent his seat becoming vacant on account of the disqualification under Article 102(1)(e) or Article 191 (v) (e) of the Constitution.)"_

इस निर्णय में संविधान के अनुच्छेद 102 की व्याख्या करते हुए सर्वोच्च अदालत का कहना था कि कोई भी सदस्य जो इस अनुच्छेद के अधीन अयोग्य घोषित होता है उसका स्थान उसी दिन से स्वत: ही रिक्त होगा जिस दिन से वह अयोग्य पाया जाएगा। इसके लिए राष्ट्रपति या राज्यपाल के निर्णय की प्रतीक्षा नहीं की जानी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय के बाद से ही यदि कोई सांसद या विधायक किसी अपराध के लिए दोषसिद्धि के चलते अयोग्य घोषित हो जाता है तो उसकी सदस्यता तत्क्षण समाप्त हो जाती है, चाहे उसने अदालत के फैसले के विरुद्ध ऊपरी अदालत में अपील ही क्यों न की हो।

इन सब बातों से यह तो साफ़ है कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त करने और उन्हें 8 साल तक चुनाव लड़ने से रोकने का यह निर्णय कोई सरकारी निर्णय नहीं है अपितु अदालत द्वारा दोषी पाए जाते ही वे संविधान के अनुच्छेद 102(1)(ङ) के तहत स्वत: ही अयोग्य हो गए हैं और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(3) के द्वारा अगले आठ सालों तक चुनाव लड़ने से वंचित कर दिए गए हैं। इस प्रकार तीनों प्रश्नों का उत्तर हमें मिल जाता है कि एक आपराधिक मामले में दोषी पाए जाने के कारण ही राहुल गांधी को अपनी संसद सदस्यता से हाथ धोना पड़ा है। इसमें कुछ भी असंवैधानिक नहीं है और सरकार इस मामले में कुछ कर भी नहीं सकती क्योंकि यद्यपि लोकसभा सचिवालय की ओर से दोषसिद्धि के दूसरे दिन अधिसूचना जारी की गई हो लेकिन राहुल गांधी तो इसे एक दिन पहले स्वत: ही अयोग्य हो चुके थे। हाँ, यदि अदालत के फैसले से असन्तुष्टि हो तो ऊपरी अदालतों में उसे चुनौती दे सकते हैं, लेकिन यह भी उनकी सदस्यता को बहाल नहीं कर पाएगा। बाकी राजनीतिक बयानबाजियाँ चलती रहें, आरोप-प्रत्यारोप चलते रहें क्योंकि भारतीय राजनीति का आनन्द इसी में निहित है।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

याज्ञवल्क्यापनिषद् (भाग-04)

गतांक से आगे...

आत्म-तत्त्वज्ञ तो किसी व्यक्ति विशेष को भी प्रणाम नहीं करता अथवा फिर ईश्वर को यह समझकर कि वह जीव के रूप में इस संसार के समस्त प्राणियों में स्थित है, घोड़े, चाण्डाल, गौ तथा गधे आदि सभी को दण्डवत् प्रणाम करता है। मांस-मेदा आदि द्वारा निर्मित, यत्र-तत्र गमन करने वाली पिटारी रूप नारी के शरीर में, जिसमें कि नसें, हड्डी एवं ग्रन्थियाँ ही स्थित हैं, कौन-सी वस्तु शोभनीय है। इस (देवी स्वरूपा नारी) की त्वचा, मांस, रक्त, अश्रु एवं नेत्र आदि पृथक-पृथक् करके (उसके शरीर के आन्तरिक अवयवों को) तो देखो। क्या वे शोभनीय लगते हैं? यदि नहीं, तो फिर क्यों इस पर व्यर्थ में इतने मुग्ध (आसक्त) हुए जाते हो। जिसके स्तनों पर लटकने वाले हार को मेरुपर्वत के शिखरों के बीच से गिरने वाली गंगाजल की धारा की उपमा दी गई है और वैसे ही वह हार परिलक्षित भी होता है।

श्मशान में तथा यत्र-तत्र दिशाओं में कटकर गिरा हुआ वही नारी का स्तन समय आने इस तरह से खाया जाता हुआ दिखाई पड़ता है, जैसे कि एक सामान्य सा खाद्य पदार्थ का टुकड़ा। पर कुत्तों द्वारा सुन्दर केशों को सुव्यवस्थित किये हुए, नेत्रों में कज्जल (काजल) लगाने वाली, दु:स्पर्श (स्पर्श के लिए दुष्प्राप्य), नेत्रों को प्रिय लगने वाली, प्रज्वलित अग्नि शिखा के सदृश जो स्त्रियाँ हैं; वे मनुष्य को तृणवत् क्षणभर में जला देती हैं। ये स्त्रियाँ दूर से ही दग्ध कर देने वाली, अत्यन्त रसयुक्त लगती हुई भी रसहीन कर देने 248 की अग्नि की लकड़ियाँ हैं, जो कि चाह दारुण (सुन्दर होने पर भी अत्यन्त दु:ख दायी) प्रतीत हो..कामदेव रूपी बहेलिये ने मानव रूपी पक्षियों को आबद्ध करने के लिए हृदय को मुग्ध (मोहित) कर देने वाला स्त्रीरूपी जाल बिछा रखा है। जन्म रूपी तलैया में निवास करने वाली, कलुषित हृदय रूपी कीचड़ में चलने वाले मनुष्य रूपी मछलियों के लिए दुर्वासना रूपी रस्सी से बंधी ये स्त्रियों मछली पकड़ने वाले काटे की भाँति है। सभी तरह के दोष रक्षों की पिटारी रूप इन दु:खों की जंजीर रूपी स्त्री से तो भगवान ही बचाये। जिसके पास स्त्री है, उसी के पास भोग की इच्छा है तथा जिसके पास स्त्री ही नहीं, वह कहाँ किसके साथ भोगे ? यदि कोई मनुष्य स्त्री का त्याग कर दे, तो यह समझना चाहिए कि उसने संसार को ही छोड़ दिया। संसार छोड़ देने पर तो प्रत्येक व्यक्ति सुखी हो ही जाता है।

क्रमश:...

आधुनिक काल की मीराबाई - महादेवी वर्मा

फ़िरदौस ख़ान

प्रख्यात कवयित्री महादेवी वर्मा की गिनती हिंदी कविता के छायावादी युग के चार प्रमुख स्तंभ सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के साथ की जाती है। होली के दिन 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फ़र्रूख़ाबाद में जन्मीं महादेवी वर्मा को आधुनिक काल की मीराबाई कहा जाता है। वह कवयित्री होने के साथ एक विशिष्ट गद्यकार भी थीं। उनके काव्य संग्रहों में नीहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, यामा और सप्तपर्णा शामिल हैं। गद्य में अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी और मेरा परिवार उल्लेखनीय है। उनके विविध संकलनों में स्मारिका, स्मृति चित्र, संभाषण, संचयन, दृष्टिबोध और निबंध में श्रृंखला की कड़ियां, विवेचनात्मक गद्य, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध शामिल हैं। उनके पु न म ुं द्रि त संकलन में यामा, द ी प ग ी त , नीलाम्बरा और आत्मिका शामिल हैं। गिल्लू उनका कहानी संग्रह है। उन्होंने बाल कविताएं भी लिखीं। उनकी बाल कविताओं के दो संकलन भी प्रकाशित हुए, जिनमें ठाकुर जी भोले हैं और आज ख़रीदेंगे हम ज्वाला शामिल हैं।

ग़ौरतलब है कि महादेवी वर्मा ने सात साल की उम्र से ही लिखना शुरू कर दिया था। उनके काव्य का मूल स्वर दुख और पीड़ा है, क्योंकि उन्हें सुख के मुक़ाबले दुख ज़्यादा प्रिय रहा। ख़ास बात यह है कि उनकी रचनाओं में विषाद का वह भाव नहीं है, जो व्यक्ति को कुंठित कर देता है, बल्कि संयम और त्याग की प्रबल भावना है।

मैं नीर भरी दुख की बदली
विस्तृत नभ का कोई कोना
मेरा कभी न अपना होना
परिचय इतना इतिहास यही
उमड़ी थी कल मिट आज चली

उन्होंने ख़ुद लिखा है, मां से पूजा और आरती के समय सुने सुर, तुलसी तथा मीरा आदि के गीत मुझे गीत रचना की प्रेरणा देते थे। मां से सुनी एक करुण कथा को मैंने प्राय: सौ छंदों में लिपिबद्ध किया था। पड़ोस की एक विधवा वधु के जीवन से प्रभावित होकर मैंने विधवा, अबला शीर्षकों से शब्द चित्र लिखे थे, जो उस समय की पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए थे। उन्होंने 1955 में इलाहाबाद में साहित्यकार संसद की स्थापना की। उन्होंने पंडित इला चंद्र जोशी की मदद से संस्था के मुखपत्र साहित्यकार के संपादक का पद संभाला। देश की आज़ादी के बाद 1952 में वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य चुनी गईं। 1956 में भारत सरकार ने उनकी साहित्यिक सेवा के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया। 1969 में विक्रम विश्वविद्यालय ने उन्हें डी लिट की उपाधि दी। इससे पहले उन्हें नीरजा के 1934 में सक्सेरिया पुरस्कार और 1942 में स्मृति की रेखाओं के लिए द्विवेदी पदक प्रदान किया गया। 1943 में उन्हें मंगला प्रसाद पुरस्कार और उत्तर प्रदेश के भारत भारती पुरस्कार से भी नवाज़ा गया। यामा नामक काव्य संकलन के लिए उन्हें देश के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें साहित्य अकादमी फ़ेलोशिप भी प्रदान की गई।

जिनपिंग की रूस यात्रा के मायने क्या हैं?

नीरज मनजीत

सोवियत संघ के विघटन से कुछेक वर्ष पहले की बात है। सोवियत राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव भारत के प्रवास पर आए थे। नई दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे एक पत्रकार ने बड़ा ही मुश्किल सवाल पूछ लिया--%अगर चीन भारत पर हमला कर देता है, तो सोवियत यूनियन अपने दोस्त भारत का साथ देगा या छोटे भाई चीन का?% जवाब काफी उलझन भरा हो सकता था, मगर गोर्बाचेव ने शांत भाव से कहा--%हम सोचते हैं कि ऐसा युद्ध कभी नहीं होगा!% इस बात को तक़रीबन पैंतीस बरस बीत गए और यह यक्ष प्रश्न वैसा का वैसा ही चीन-रूस-भारत के त्रिकोण के सामने खड़ा है। इस वक़्त यदि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से यह सवाल किया जाए, तो उनका जवाब जानना काफी दिलचस्प हो सकता है, क्योंकि रूस इस समय अपने इतिहास के सर्वाधिक कठिन दौर में खड़ा है। यूक्रेन युद्ध में उलझने के बाद पुतिन पर दुनिया के सबसे ताक़तवर सैन्य संगठन नाटो और अमेरिका का भारी दबाव पड़ रहा है। रूस पर दुनियाभर के प्रतिबंध लगा दिए गए हैं और उसे नितांत अलग-थलग किया जा रहा है।

ऐसे हालात में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का रूस दौरा पुतिन के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। दिलचस्प बात यह भी है कि चीन इस वक़्त वैश्विक बिरादरी में रूस के बड़े भाई के रोल में है। जिनपिंग की मॉस्को यात्रा के पीछे दो ज़ाहिराना और दो छिपे मक़सद थे। ज़ाहिरी तौर पर जिनपिंग शांति के एक मसीहा के तौर पर मॉस्को में थे। दूसरा जाहिराना मक़सद था कि वे रूस के साथ कारोबार को नए शिखरों पर ले जाना चाहते थे। छिपा हुआ पहला मक़सद यह था कि वे भी नाटो देशों, अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया के सम्मिलित दबाव से उबरने की कोशिशों में रूस जैसे ताक़तवर देश का साथ चाहते हैं। दूसरा छिपा मक़सद था कि वे अमेरिका और नाटो के ख़िलाफ़ एक मजबूत ब्लॉक खड़ा करना चाहते हैं। जिनपिंग और उनके सहयोगी अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कई बार बहुध्रुवीय विश्व समुदाय की वकालत कर चुके हैं। पिछली सदी के आख़िरी दशक में वामपंथी प्रबुद्धजनों ने अमेरिका के ख़िलाफ़ रूस-भारत-चीन के सम्मिलित शक्तिशाली त्रिकोण को खड़ा करने का विचार दिया था। मगर यह विचार आगे नहीं बढ़ सका था। चीन और रूस तो इस विचार से सहमत थे, पर नई दिल्ली में सरकारों की विदेशनीति बदलती रहने से भारत इस त्रिकोण में नहीं जुड़ सका।

जिनपिंग की मॉस्को यात्रा के बाद रूस और चीन एक-दूसरे के काफी नज़दीक आएँगे, उनके बीच व्यापार में भी काफी बढ़ोत्तरी होगी, यह तय है। निश्चित रूप से रूस को इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोप में रूस के कारोबार को बहुत बड़ा नुक़सान हुआ है। चीन को गैस और कच्चे तेल की सप्लाई बढ़ाने से रूस इस नुक़सान की थोड़ी बहुत भरपाई कर सकेगा। इधर चीन को भी इस सस्ते माल का फ़ायदा होगा। मॉस्को में पुतिन और जिनपिंग के बीच क़रीब तीन घंटे की बातचीत हुई है। इसमें कोई संदेह नहीं कि कारोबार के अलावा दोनों महा-राजनेताओं के बीच अमेरिका के विरुद्ध एक वैश्विक खेमा तैयार करने की संजीदा बातचीत हुई होगी। यद्यपि वार्ता के बाद संयुक्त साझा बयान में ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है। इस बातचीत के बाद शीतयुद्ध के दौर वाला वारसा संधि जैसा कोई संगठन तैयार होगा, इसकी कोई उम्मीद अभी तो नज़र नहीं आ रही। इस सदी की शुरुआत के बाद से ही धीरे धीरे अमेरिका ने नाटो का विस्तार करके अपना एक अभेद्य ब्लॉक खड़ा कर लिया है। भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश, जो नाटो में शामिल नहीं हैं, उन्हें क्वाड और आसुक संगठनों के जरिए अपरोक्ष रूप से इस ब्लॉक के साथ जोड़ लिया गया है।

जहाँ तक जिनपिंग के शांति प्रस्ताव की बात है, फिलहाल तो रूस यूक्रेन के बीच सीज़फायर होता दिखाई नहीं पड़ रहा है। जिनपिंग मॉस्को जाने से पहले वैश्विक समुदाय को यह जताना चाहते थे कि वे जो बाइडेन की पीलैंड यात्रा के विलोम इस युद्ध की आग में घी डालने के बजाए एक शांतिदूत के रूप में रूस जा रहे हैं। दरअसल पिछले महीने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेन्स्की ने जिनपिंग से अपील की थी कि वे रूस पर दबाव डालकर युद्ध ख़त्म करवाएँ। जिनपिंग की पहल पर कुछ दिनों पहले ईरान और यूएई बरसों पुरानी दुश्मनी भूलकर अच्छे दोस्तों की तरह रहने पर राजी हुए थे। वैश्विक समुदाय में इसे चीन की एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा था। इस उपलब्धि से उत्साहित जिनपिंग को ऐसा लगा कि वे एक बड़े पीस मेकर बनकर मॉस्को जा सकते हैं। उन्होंने इस संदर्भ में पुतिन से अपील भी की है, मगर इस युद्ध के धागे काफी उलझ चुके हैं। मार्च के पहले हफ़्ते नई दिल्ली में जी-20 की बैठक में ही यह साफ़ हो गया था कि जिनपिंग के शांति प्रस्ताव की कोई अहमियत नहीं है। अमेरिका यह कतई नहीं चाहता कि इसी यथास्थिति को मानकर सीजफायर हो जाए। ज़ाहिर है कि नाटो में शामिल होने को लालायित जेलेन्स्की अमेरिका की उपेक्षा करके चीन की बात कतई नहीं मानेंगे।

दरअसल रूस ने यूक्रेन के चार महत्वपूर्ण इलाकों--दोनेत्स्क, लुहान्स्क, खेरसन और जियोरिज़्झिया--पर कब्ज़ा किया हुआ है। जेलेन्स्की और अमेरिका की पहली शर्त यही है कि रूस पहले इन इलाकों को ख़ाली करे, तभी शांतिवार्ता आगे बढ़ सकती है। जबकि पुतिन कहते हैं कि इन इलाकों में रूसी लोगों की बहुलता है, इसलिए इन्हें रूस में शामिल कर लिया गया है। पुतिन इन इलाकों में यूएन की निगरानी में जनमत संग्रह कराने की बात कह रहे हैं। ज़ाहिर है कि इस तनातनी और अहम की लड़ाई में युद्ध रुकने के आसार दिखाई नहीं पड़ रहे।

गांधी आज

शौच

सड़क पर पाखाना फिरने की आदत तो हर्गिज न होनी चाहिए। खुली जगह में लोगों के देखते पाखाना फिरना बल्कि बच्चों तक को फिराना असभ्यता है। इसलिए प्रत्येक गाँव में घूर की जगह में सस्ते से सस्ते पाखाने बनवाने चाहिए और उन्हें नियमित रूप से रोज साफ कराना चाहिए। जो जंगल ही जाना हो तो गाँव से एक मील दूर जहाँ आबादी न हो वहाँ जाना चाहिए। जंगल बैठते वक्त गड्ढा खोद लेना चाहिए और क्रिया पूरी करने के बाद मलपर खूब मिट्टी डाल देनी चाहिए। समझदार किसान को चाहिए कि अपने खेतों में ही पूर्वोक्त प्रकार के पाखाने बनाकर अथवा जंगल जाकर मैला गाड़े और बे-पैसे की खाद ले। इसके सिवा बालक, बीमार तथा बेवक्त के इस्तेमाल के लिए हर घर के साथ एक पाखाना ज़रूर होना चाहिए। उसके लिए कनस्तर के अद्धे या मिट्टी के गमले का उपयोग किया जा सकता है और उसमें भी हर आदमी कोपाखाना फिरने के बाद काफी मिट्टी डाल देनी चाहिए। कनस्तरों को रोज किसी खेत में गड्ढा खोदकर उसमें खाली करना चाहिए और गड्ढे को साफ मिट्टी से भर देना चाहिए। कनस्तर को इस तरह साफ करना चाहिए कि बदबू न रहे। पाखाने में पानी और पेशाब के लिए अलग डिब्बा या डोल रखना चाहिए जिससे बाहर जरा भी गीला न होने पाए। संडास पाखाने बिलकुल बेकार हैं। इतनी गहराई में खाद पैदा करनेवाले जंतु नहीं रहते। इससे उनमें गंदी गैस पैदा होती और हवा को बिगाड़ती है। गलियों में पेशाब करना पाप समझना चाहिए। अत: इसके लिए काही मिट्टी भरे हुए मटके रखने चाहिए, जिससे न बदबू आए, न छींटें इसके आगे के कितने ही प्रकरण गांधीजी लिखित गामड़ानी वहारे लेखमाला के आधार पर लिखे गए हैं। ग्राम सेवा के नाम से यह पुस्तिका प्रकाशित हो चुकी है।

संक्षिप्त समाचार

बच्चों के कल्याण के लिए निरंतर करें कार्य - राज्यपाल

रायपुर। राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन से आज राजभवन में छत्तीसगढ़ राज्य योजना बाल कल्याण परिषद के उपाध्यक्ष श्री चंद्रेश शाह के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य भेंट की और बाल विकास परिषद के उद्देश्य एवं कार्यों के बारे में जानकारी दी। राज्यपाल ने बाल कल्याण परिषद द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। उन्होंने इसी प्रकार बच्चों के कल्याण के लिए कार्य करते रहने को कहा क्योंकि बच्चे ही देश का भविष्य है। बाल कल्याण परिषद के सचिव ने बताया कि रायपुर में स्पीच थेरपी केंद्र 2 वर्ष से संचालित है जहां कम शुल्क पर मूक बधिर बच्चों का उपचार किया जाता है। इसके अलावा परिषद द्वारा 4 बाल गृह संचालित हैं जिसमें 2 बालिका और 2 बालक गृह शामिल हैं। इस अवसर पर डॉ. अशोक त्रिपाठी, श्रीमती इंदिरा जैन, श्री प्रकाश अग्रवाल, श्री राजेन्द्र निगम, श्रीमती प्रभा सेन्द्रे, श्रीमती संगीता जग्गी, श्रीमती श्वेता सिंह, श्रीमती मणी शर्मा, श्रीमती पूजा मिसालवार भी उपस्थित थे।

जामा मस्जिद में हुआ पहला रोजा इफ्तार

कोरबा। इस्लाम का मुबारक और पाक महीना रमजान शुरू हो चुका है। रमजान का महीना मुस्लिम समुदाय के लिए काफी महत्व रखता है। इसमें लोग पूरे महीने रोजा रखते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं। मुस्लिम समुदाय के बीच रमजान के महीने का बेहद खास महत्व होता है। रमजान को रमादान, कुरान का महीना और रोजे का महीना भी कहा जाता है। इस पूरे महीने में लोग रोजा रखते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं। इस्लामिक कैलेंडर में चांद का खास महत्व होता है और रमजान के महीने की शुरुआत चांद के दिखाई देने के बाद ही होती है। रमजान के साथ ही कई त्योहार मनाने से पहले भी चांद देखा जाता है। कोरबा सुन्नी मुस्लिम जमात के सदर हाजी अखलाक खान असरफी ने जारी बयान में बताया कि जामा मस्जिद में पूरे रमजान रोजा इफ्तार का इंतेजाम किया जाएगा जिसका आज पहला दिन था सैकड़ों लोगो ने रोजा इफ्तार किया। इस मौके पर सुन्नी मुस्लिम जमात के सरपरस्त कारी सैयद शब्बीर अहमद अशरफी, जनरल सेक्रेटरी जुम्मन खान रिजवी, सेक्रेटरी सैयद अशफाक अली व अब्दुल मजीद ताज, एहसान खान, बाबा खान, बिलाल खान, शेख मंसूर, आरिफखान, सेखु समेत अन्य मौजूद रहे।

छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ के जिला अध्यक्ष बने मुकेश

कोरबा। हरदीबाजार क्षेत्र निवासी मुकेश जायसवाल को छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ के जिला अध्यक्ष बनाया गया है। मुकेश वर्तमान में जिला बस यूनियन के जिला अध्यक्ष भी है। इस तरह वे साथ.साथ दोनों पदों के जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ के जिला अध्यक्ष के रूप में लंबे समय से ब्रजेश त्रिपाठी पदस्थ थे। करीब एक दशक बाद महासंघ के जिला अध्यक्ष पद में बदलाव हुआ है। छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष अनवर अली ने संरक्षक गुरू चरण सिंह होरा, संयोजक नरेंद्र पाल सिंह गरचा समेत अन्य पदाधिकारियों की सहमति से मुकेश जायसवाल को जिला अध्यक्ष नियुक्त करने का आदेश शुक्रवार को जारी किया। मुकेश जायसवाल शिवम बस सर्विस के संचालक है। उनके जिलाध्यक्ष बनने पर महिंद्रा बस सर्विस के प्रफुल्ल तिवारी, विरक बस सर्विस के लखविंदर पाल सिंह, साईं बस ट्रांसपोर्ट के केशर स्वामी, प्रेम स्वामी, आशीर्वाद बस के अनीश शर्मा, धनेश्वर साहू समेत सभी बस ऑपरेटर व मालिकों समेत एजेंटों ने हर्ष व्यक्त करते हुए उनका स्वागत सम्मान किया।

बच्चों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य करें- राज्यपाल

रायपुर, 26 मार्च। राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन से आज राजभवन में छत्तीसगढ़ राज्य योजना बाल कल्याण परिषद के उपाध्यक्ष श्री चंद्रेश शाह के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य भेंट की और बाल विकास परिषद के उद्देश्य एवं कार्यों के बारे में जानकारी दी। राज्यपाल ने बाल कल्याण परिषद द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। उन्होंने इसी प्रकार बच्चों के कल्याण के लिए कार्य करते रहने को कहा क्योंकि बच्चे ही देश का भविष्य है । बाल कल्याण परिषद के सचिव ने बताया कि रायपुर में स्पीच थेरपी केंद्र 2 वर्ष से संचालित है जहां कम शुल्क पर मूक बधिर बच्चों का उपचार किया जाता है। इसके अलावा परिषद द्वारा 4 बाल गृह संचालित हैं जिसमें 2 बालिका और 2 बालक गृह शामिल हैं। इस अवसर पर डॉ. अशोक त्रिपाठी, श्रीमती इंदिरा जैन, श्री प्रकाश अग्रवाल, श्री राजेन्द्र निगम, श्रीमती प्रभा सेन्द्रे, श्रीमती संगीता जग्गी, श्रीमती श्वेता सिंह, श्रीमती मणी शर्मा, श्रीमती पूजा मिसालवार भी उपस्थित थे।

कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिव यादव कल आएंगे

रायपुर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं प्रदेश प्रभारी सचिव डॉ. चंदन यादव दिनांक 26 मार्च 2023 रविवार को इंडिगो के नियमित विमान सेवा द्वारा शाम 5.10 बजे रायपुर पहुंचेंगे। शाम 5.45 बजे सर्किट हाउस रायपुर में कांग्रेसजनों से भेंट एवं चर्चा करेंगे।

देश-दुनिया की वाहन उद्योग की बड़ी भूमिका - मुख्यमंत्री

- ऑटो एक्सपो 2023 का हुआ उद्घाटन,सुभाष धुप्पड़ को लाइव टाइम अचिवमेंड अवार्ड
- मुख्यमंत्री ने दिलाई हरित क्रांति की शपथ,हर गाड़ी की खरीदी पर दिया जायेगा एक पौधा

रायपुर। ऑटो एक्सपो 2023 का उद्घाटन साइंस कालेज मैदान में करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आज देश और दुनिया जिस गति से आगे बढ़ रही है उसमें वाहन उद्योग की बड़ी भूमिका है। पहले शहर में, मोहल्ले में और गांव में किसी – किसी के पास गाड़ी होती थी आज स्थिति यह है कि घर में चार सदस्य है तो सबके पास अलग – अलग गाड़ी है। समय बदला है, समाज में भी बदलाव आया है और गाडियों की संख्या भी बढ़ी है। छत्तीसगढ़ सरकार ने परिवहन उद्योग में बहुत सारी सुविधाएं और छूट प्रदान की है। आजीवन रोड टैक्स वाली वाहन की खरीदी पर 50 फीसदी छूट का सीधा फायदा आम जनता को मिलेगा। इस मौके पर राडा की ओर से यह घोषणा भी किया गया कि हर गाड़ी खरीदने वाले को एक पौधा दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ ऑटो केयर के संचालक सुभाष धुप्पड़ को लाइफ टाइम अचिवमेंट अवार्ड से नवाजा गया।

श्री बघेल ने कहा कि कोरोना काल में भी छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य था जब व्यापार, परिवहन व अन्य उद्योग व्यापार बंद हो रहे थे लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार का रेवन्यू 11 सौ करोड़ से बढ़कर 16 सौ करोड़ रहा। यह बेहतर वित्तीय प्रबंधन और रणनीति का परिणाम था। बढ़ते प्रदूषण के प्रति भी सचेत करते हुए उन्होंने ऑटो एक्सपो में सभी को हरितक्रांति के लिए शपथ दिलाई। मार्च बीतने को है लेकिन देश में मार्केट से लोन नहीं लेने वाले तीन राज्य है ओडिशा, त्रिपूरा और छत्तीसगढ़ यह हमारे के लिए गौरव की बात है। आज हम गोबर से भी पैसा कमाने की बात कर सकते है। छत्तीसगढ़ में परिवहन सेवाएं आज यहां तक सुविधाजनक हो गई है कि अधिकांश सुविधाएं ऑनलाइन घर तक मुहैय्या कराई जा रही है।वन,आवास-पर्यावरण एवं परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने भी ऑटो एक्सपो के लिए शुभकामनाएं देते हुए रोड टैक्स में दी गई छूट का लाभ लेने का आग्रह किया। उन्होने कहा कि परिवहन विभाग आज लोगो को घर तक आनलाइन रजिस्ट्रेशन पहुंचा रहा है। स्वागत भाषण देते हुए राडा के अध्यक्ष विवेक गर्ग ने कहा कि आटो एक्सपो में डीलर्स,कंपनी,स्पेयर पार्ट्स विक्रेता से लेकर ग्राहक तक को एक प्लेटफार्म उपलब्ध होता है। आज 62 सदस्यों का भरा पूरा परिवार है और 8000 लोगों को सीधे रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। इस सेक्टर का राज्य के राजस्व में 800 करोड़ का सालाना जीएसटी का योगदान है। वाहन बेंचने से हटकर जनहितकारी कार्यो में भी राडा सदस्यों की सहभागिता रही है और निरंतर जारी रहेगा। फाडा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीषराज सिंघानिया ने बताया कि सभी के सामूहिक प्रयास और मुख्यमंत्री जी की लीडरशिप का परिणाम रहा कि कोविडकाल में छग की आटोमोबाइल्स इंडस्ट्री ने 16.5 प्रतिशत का ग्रोथ दर्शाया। आटो उद्योग को और प्रोत्साहन करने के लिए उन्होने मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से नवा रायपुर में जमीन की मांग रखी। छग चेंबर आफ कामर्स के अध्यक्ष अमर परवानी ने कहा कि गर्व का दिन है जब आटो एक्सपो आज इस स्वरूप में आयोजित हो रहा है। इसका श्रेय उन्होने बिजनेस के साथ प्रदेश के मुखिया को भी दिया। चार साल में जो वातावरण प्रदेश में बना है इससे आज स्थिति यह है कि शहर गांव पर डिपेंड कर रहा है। साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा मार्केट रायपुर में बनने जा रहा है। ट्रेडिश्नल बाजार को सुधारने के लिए राज्य सरकार के साथ नगर निगम रायपुर ने भी पूरा सहयोग किया है। इस मौके पर राडा की ओर से यह घोषणा भी किया गया कि हर गाड़ी खरीदने वाले को एक पौधा दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ ऑटो केयर के संचालक सुभाष धुपड़ को लाइफ टाइम अचिवमेंट अवार्ड से नवाजा गया।रायपुर ऑटोमोबाइल्स डीलर्स एसोसिएशन (राडा) द्वारा आयोजित ऑटो एक्सपो 2023 का आयोजन साइंस कालेज मैदान में 24 मार्च से 5 अप्रैल तक किया गया है। आजीवन रोड टैक्स वाली वाहन की खरीदी पर एक्सपो अवधि के दौरान 50 फीसदी छूट देने की एक बड़ी सौगात छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से दी गई है। इसका लाभ अधिकाधिक लोगों को मिल सके इसलिए एक्सपो की अवधि अब 5 अप्रैल तक रखी गई है। राडा ने मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल, वन आवास व पर्यावरण एवं परिवहन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर, परिवहन सचिव एस प्रकाश, परिवहन आयुक्त दीपांशु काबरा के प्रति आभार व्यक्त किया है। साथ ही लोगों से अपील की है इस छूट का अधिकाधिक लाभ लें। इस अवसर पर वन आवास व पर्यावरण एवं परिवहन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर, संसदीय सचिव एवं विधायक विकास उपाध्याय, महापौर एजाज ढेबर, आरडीए अध्यक्ष सुभाष धुपड़, पूर्व विधायक राजकमल सिंघानिया, बालीवुड सेलिब्रिटी शाहजान पदमसी, छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कामर्स के अध्यक्ष अमर परवानी, फाडा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीषराज सिंघानिया, पूर्व विधायक राजकमल सिंघानिया, गोदावरी एमोबिलिटी के एमडी सिद्धार्थ अग्रवाल, इफको टोकयो इंश्योरेंस कंपनी के एचओ सूरी जी,चोलामंडलम इनवेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के बिजनेस हेड अमन शर्मा, एसबीआई के डीजीएम राकेश कुमार यादव, रायपुर मोटर मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष सुधीर अग्रवाल, राडा के पूर्व अध्यक्ष शशांक शाह, अनिल अग्रवाल, जयेश पिथालिया, राडा बोर्ड मेंबर्स व राडा मेंबर्स उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश होंगे जस्टिस सिन्हा

बिलासपुर। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जस्टिस रमेश सिन्हा अब छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे। 19 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के कालेजियम ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाए जाने हेतु उनके नाम की अनुशंसा की थी। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे प्रीतिंकर दिवाकर को इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। हालांकि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में पूर्णकालिक चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्ति से पहले जस्टिस गौतम भादुड़ी को कार्यवाहक चीफ जस्टिस बनाया गया था। नए चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जस्टिस हैं। उन्होंने सन 1990 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एलएलबी की डिग्री ली। इसके पश्चात आठ सितंबर 1990 को अधिवक्ता के रूप में नामांकन करवा वकालत की शुरुआत की। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में उन्हें प्रैक्टिस करते हुए उन्हें क्रिमिनल व सिविल मेटर में दक्षता हासिल हुई। इन मामलों में अधिवक्ता के रूप में काफी प्रसिद्ध हुए। 21 साल की वकालत के बाद बार कोटे से 21 नवंबर 2011 को वह इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदस्थ हुए। दो साल से पहले ही छह अगस्त 2013 को उन्होंने स्थायी न्यायाधीश के रूप में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में काम शुरू किया। वह सदस्य प्रशासनिक आयोग लखनऊ के पद पर भी रहे हैं। उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि चार सितंबर 2026 है।

26 से 31 तक सुयश अस्पताल में निःशुल्क कटे होंठ और तालू सर्जरी शिविर

रायपुर। सुयश अस्पताल में 26 से 31 मार्च तक द फ्यूचर ऑफ स्माइल्स मिशन के तहत निःशुल्क कटे होंठ और तालू सर्जरी शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में निशुल्क सर्जरी के लिए 28 मार्च तक 8918279407 एवं 8962124793 नंबर पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यह तीसरा निःशुल्क कटे फटे सर्जरी शिविर होगा जो सुयश अस्पताल में आयोजित किया जाएगा।सुयश हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉ. विवेक केशरवानी ने पत्रकारवार्ता के दौरान बताया कि सुयश अस्पताल, ऑपरेशन स्माइल इंक और इंगा हेल्थ फाउंडेशन ने 2018 में छत्तीसगढ़ में कटे होंठ और कटे तालु से पीड़ित बच्चों के विशाल बैकलॉग के इलाज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से एक साझेदारी की थी। तब से, छत्तीसगढ़ में 226 बच्चों को सुरक्षित सर्जरी और बाल चिकित्सा, एनेस्थीसिया, प्लास्टिक सर्जरी, नर्सिंग, दंत चिकित्सा, पोस्ट-ऑपरेटिव देखभाल, मनोसामाजिक देखभाल और भाषण परामर्श सहित लगभग 400 रोगियों को छत्तीसगढ़ में व्यापक देखभाल परामर्श प्रदान किया गया है।

सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ध्वस्त

धमतरी। ग्राम पंचायत परेवाडीह में भाजपा समर्थित सरपंच खिलेश्वरी साहू के खिलाफ विपक्ष द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव गिर जाने के बाद गांव में बवाल मच गया जो देर रात तक जारी रहा। सूचना मिलने पर पुलिस तत्काल वहां पर पहुंची लेकिन ग्रामीणों और पुलिस के बीच भी जूतम पैचार हुआ। जिसके बाद अलसुबह मामला शांत हुआ और पुलिस ने पंचायत भवन से किसी तरह सरपंच, उसके पति और पंचों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाला। गांव में स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बताई गई है और पुलिस का पहरा जारी है। धमतरी ब्लॉक के परेवाडीह में जिला प्रशासन की ओर से छात्रों के हित में उद्यानिकी कॉलेज खोलने की घोषणा कर प्रारंभिक तैयारी शुरू की गई जिसके विरोध में गांव के एक वर्ग द्वारा विरोध किया जा रहा था। ग्राम विकास

समिति को विश्वास में लिए बगैर कॉलेज के लिए पंचायत प्रस्ताव बनाने की बात को लेकर सरपंच के खिलाफ विरोध शुरू कर दिया। पिछले दिनों कलेक्ट्रेट का घेराव भी किया।

इसके बाद पंचों ने सरपंच खिलेश्वरी साहू पति देवेन्द्र के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का आवेदन दिया था। शुक्रवार को नियत तिथि में एसडीएम के निर्देश पर गांव में अविश्वास प्रस्ताव के लिए पंचों का सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें सरपंच के विरोध में लाया गया अविश्वास प्रस्ताव ध्वस्त हो गया। वोटिंग की प्रक्रिया में सरपंच की कुर्सी बच गई। इसके बाद गांव में बवाल मच गया। अविश्वास प्रस्ताव को देखते हुए सुबह से ही गांव में गहमा-गहमी का माहौल रहा। इसके बाद ग्राम पंचायत के आगे ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। देखते ही देखते ग्रामीणों की भीड़ ने उग्र रूप धारण कर लिया और सरपंच खिलेश्वरी साहू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया।

सुहाग की मनोकामना के लिए अग्रवाल महिला मंडल ने मनाया गणगौर त्योहार

रायपुर। अग्रवाल महिला मंडल की महिलाओं ने अपने सुहाग की मनोकामना के लिए ने गणगौर का त्योहार मनाया और प्रतियोगिताएं भी खेली। जिसमें गणगौर प्रतियोगिता में निकिता अग्रवाल प्रथम रही, वहीं रैंप वॉक गुढियारी की प्रीति अग्रवाल व डांस में रामसागरपारा की प्रीति अग्रवाल ने प्रथम पुरस्कार जीता। प्रचार प्रसार मंत्री ज्योति अग्रवाल ने बताया कि गणगौर का त्योहार मनाने के लिए महिलाएं 16 दिनों तक गणगौर की पूजा करती है और आखिरी दिन सोलह सिंगार करके अपने-अपने सुगाहों के साथ गणगौर का त्यौहार मनाती है। सुहाग की मनोकामना के लिए महिलाओं ने गणगौर का त्योहार मनाया और अपनी-अपनी गणगौर को सजाकर गोराजी और ईश्वरजी को साथ लेकर आए और गीत गाए आई गणगोर की बहार खुशियां लाई अपार दिल की कलियां सज गई सखियां हाथों में मेहंदी सजे रसोई पकवानों से...। इसके बाद रैंप वॉक का आयोजन भी किया गया है जिसमें महिलाओं ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इसके अलावा डांस की भी प्रतियोगिता आयोजित की गई।

राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त होना संविधान सम्मत - जितेन्द्र वर्मा

दुर्ग। राहुल गांधी को न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए जाने के खिलाफ देशभर में कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए जिला भाजपा अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा ने कहा कि कांग्रेस को न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है और वह अपने प्रदर्शनों से देश की न्यायपालिका को दबाव में लाना चाहती है। राहुल गांधी द्वारा कहे गए अपमानजनक कथन न्यायालय में सत्य सिद्ध हुए जिससे उन्हें दोषी करार देते हुए दंडित किया गया है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई पूर्वाग्रह नहीं है, ये पूर्णतः न्यायिक प्रक्रिया का परिणाम है परंतु कांग्रेस पार्टी इसमें राजनीति कर रही है। जिला भाजपा अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा ने दुर्ग विधायक अरुण वोरा के उस बयान को हास्यास्पद बताया, जिसमें अरुण वोरा ने राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त होने को अघोषित आपातकाल बताया है। जितेंद्र वर्मा ने कहा कि अरुण वोरा तीन तीन बार विधायक होने के बावजूद पूरी तरह से अपरिपक्व है और उन्हें ना तो संविधान का ज्ञान है ना ही संसदीय परंपरा का ज्ञान है। जिला भाजपा अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा ने कहा कि दुर्ग शहर के विधायक अरुण वोरा को यह जानकारी होनी चाहिए कि जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 के मुताबिक अगर किसी भी मामले में सांसद और विधायक को 2 साल से ज्यादा की सजा मिलती है तो उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी और सजा खत्म होने के 6 साल बाद तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकता है, यह कानून सालों पहले कांग्रेस पार्टी द्वारा ही देश में लागू किया गया था। राहुल गांधी पर भी यही कानून लागू किया गया है। पूर्व में लालू प्रसाद यादव के साथ भी यही हुआ है। कांग्रेस नेताओं के मुंह से आपातकाल की बात अच्छी नहीं लगती क्योंकि आपातकाल तो जनसंघ ने 1977 में झेल था जब कांग्रेस ने देश से लोकतंत्र को खत्म करके देश के सारे निर्दोष नेताओं को 19 महीने लगातार बिना किसी न्यायालय के आदेश के जेल में डाल दिया था। जिला भाजपा अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा ने कांग्रेस पार्टी को समझाइश देते हुए कहा कि गांधी परिवार का सदस्य होने का यह मतलब नहीं है कि राहुल गांधी कानून से बड़े हैं, जिस प्रकार देश की जनता कानून से संचालित होती हैं वैसे ही राहुल गांधी को भी कानून से ही संचालित होना पड़ेगा।

पौष्टिक पोषक आहार से महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य में आया सुधार

रायपुर। महिलाओं एवं बच्चों में कुपोषण और एनीमिया की समस्या को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल पर शुरू किए गए मुख्यमंत्री सुपोषण योजना से महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य में बड़ा सुधार आ रहा है। आदिवासी बहुल दंतेवाड़ा जिले में 4 हजार 412 बच्चों ने कुपोषण को मात दे दी है। योजना से अब तक यहां 94 हजार 828 महिलाओं और बच्चों ने लाभ उठाया है। मुख्यमंत्री सुपोषण योजनामुख्यमंत्री सुपोषण अभियान का मुख्य उद्देश्य स्थानीय स्तर पर उपलब्ध पौष्टिक भोजन, प्रोटीन, आयरन युक्त खाद्य सामाग्रियों को दैनिक जीवन में शामिल कर कुपोषण एवं एनीमिया की दर में कमी लाना है। इसके साथ ही जन-सामान्य में कुपोषण एवं एनीमिया के विरूद्ध जन-जागरूकता लाकर इससे निपटने के लिए वातावरण तैयार करना है। योजना के तहत दंतेवाड़ा जिले में सुपोषण केंद्रों के माध्यम से 1 से 3 वर्ष के सामान्य एवं कुपोषित बच्चे, शिशुवती माताओं एवं आंगनबाड़ी केन्द्र के माध्यम से 3 से 6 वर्ष के बच्चे तथा गर्भवती माताओं को पौष्टिक आहार से लाभांवित किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा बच्चों और माताओं को योजना के तहत प्रतिदिन निःशुल्क पौष्टिक भोजन दिया जा रहा है। खाने में अंडे, गुड़ और मूंगफली से बने पौष्टिक लड्डू दिए जा रहे हैं। बच्चों, महिलाओं को पौष्टिक आहार मिलने से कुपोषण की दर घटी है।

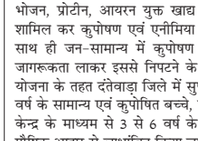

आदिवासी समाज हित और पेसा कानून को मजबूत बनाने का कार्य करें-लखमा

सामाजिक जागरूकता के लिए शिक्षा बहुत जरूरी

रायपुर, 25 मार्च। वाणिज्यिक कर (आबकारी) एवं उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने अनुसूचित जनजाति सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सामाजिक एकता के साथ समाज सुधार का कार्य करें और समाज के हित में पेसा कानून को मजबूत बनाने के लिए एकजुट होकर कार्य करें। लखमा आज रायपुर के शहीद स्मारक भवन में छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा आयोजित अनुसूचित जनजाति सम्मेलन को संबोधित कर रहे थें। मंत्री लखमा ने कहा कि विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर गत वर्ष राज्य में पेसा कानून लागू किया गया। पेसा कानून का राज्य में प्रारंभिक काल है। आदिवासी समाज के हित में सामाजिक एकता के साथ इसमें सुधार के लिए अनुसूचित जनजाति आयोग को सुझाव दे। आयोग उनके सुझाव को सरकार तक पहुंचाने का कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज के हित में सरकार ने कोशिश की है कि आदिवासी क्षेत्रों में समाज के स्थानीय निवासियों को वहीं पर सरकारी नौकरी मिले। सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए आदिवासी समाज को सरकार ने आरक्षण की व्यवस्था की है। आदिवासी संस्कृति और सामाजिक संरक्षण के लिए सरकार द्वारा देवगुड़ी और घोटुल निर्माण के लिए राशि स्वीकृत की जा रही है। लखमा ने कहा कि महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज और स्वर्गीय राजीव गांधी के पंचायती राज का सपना ग्राम विकास से ही पूरा होगा। पंचायती राज व्यवस्था में सरपंच ही ग्राम का विकास कर सकता है। उन्होंने कहा कि सामाजिक जागरूकता के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है।

सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि आयोग के वार्षिक अधिवेशन में उसके कार्यों की प्रगति का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया जाता है। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज के पास कई चुनौतियां हैं। देश की आजादी के बाद आदिवासियों को बराबरी का दर्जा देने के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण का मौका दिया गया। छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष भानुप्रताप सिंह ने कहा कि आयोग प्रदेश में अनुसूचित जनजाति वर्ग के संवैधानिक हितों की रक्षा के लिए सजग प्रहरी के रूप में निरंतर कार्यरत् है। आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन एवं शिकायत पत्रों पर संज्ञान लेकर आयोग कार्यालय एवं जिलों में कैम्प कर सुनवाई की गई, जिससे अनुसूचित जनजाति वर्ग के पीड़ित व्यक्तियों को न्याय मिला है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में माह फरवरी 2023 की स्थिति में 1728 प्रकरण पंजीबद्ध है, जिसकी नियमित सुनवाई पर प्रकरणों का निराकरण किया जा रहा है। आयोग द्वारा 01 और 02 दिसंबर 2021 को छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार नियम-1996) (पेसा एक्ट) के संबंध में आदिवासी समाज प्रमुखों एवं विशेषज्ञों की कार्यशाला का आयोजन किया गया। आयोग के पदाधिकारियों द्वारा जिलों का भ्रमण कर समाज के लोगों से भेंट-मुलाकात की जाती है और उनकी समस्याओं से अवगत होकर उनका समाधान करने का प्रयास किया जाता है। इसके साथ प्रकरणों की नियमित सुनवाई कर निराकरण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बस्तर संभाग के सुकमा जिले के 98 आदिवासी परिवार सलवा जुडूम आंदोलन के कारण अपने घर-द्वार छोड़कर आंध्रप्रदेश एवं तेलंगाना राज्य में पलायन कर गए थे।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने दागे सवाल

पिछड़े वर्ग के अपमान पर राहुल गांधी ने माफी क्यों नही मांगी

रायपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व सांसद अरुण साव ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा राहुल गाँधी की लोक सभा सदस्यता रद्द हो गई है। वैसे उनकी सदस्यता तभी रद्द हो गई थी जब सूरत की एक अदालत ने राहुल गाँधी को देश के समग्र ओबीसी समाज का अपमान करने के मामले में दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। राहुल गाँधी की सदस्यता जाने में भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है। उनकी सदस्यता अदालत के फैसले के साथ ही प्रभावी हो गई थी, बस प्रक्रिया का पालन करते हुए उसे नोटिफाई करना था जिसे लोक सभा सचिवालय ने कर दिया ।

रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल्स एक्ट 1951 के तहत अगर किसी सांसद या विधायक को किसी अपराध में दोषी ठहराया जाता है और उसे 2 साल या इससे ज्यादा की सजा सुनाई जाती है, तो दोषी करार होते ही उसकी संसद या विधान सभा की सदस्यता तत्काल प्रभाव से रद्द हो जाती है। 2013 में लिली थॉमस वर्सेज यूनियन ऑफ़ इंडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय पर मुहर लगाई थी। सजा का ऐलान होते ही पूर्व कांग्रेस के मंत्री वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने भी मान लिया था कि राहुल गाँधी एक सांसद के तौर पर अयोग्य हो चुके हैं। राहुल गाँधी की संसद सदस्यता जाने में कांग्रेस पार्टी की भी भूमिका है। ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस पार्टी खुद यही चाहती थी कि राहुल गाँधी की लोक सभा सदस्यता चली जाए। पवन खेड़ा वाले मामले में केवल 15 मिनट में कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट चली जाती है लेकिन इस मामले में लगभग 24 घंटे से भी ज्यादा समय तक कांग्रेस पार्टी ने किसी भी अदालत में कोई अपील नहीं की। लोकसभा चुनाव के दौरान 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक में बेंगलुरु के पास कोलार में राहुल गाँधी ने देश के ओबीसी समाज और तेली समाज के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और उनके सरनेम को लेकर उनका अपमान किया था। इसको लेकर देश का ओबीसी समाज और तेली समाज काफी आक्रोशित था। अदालत के फैसले ने उन्हें सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया है। इन चार सालों में ऐसे कई मौके आये जब राहुल गाँधी ओबीसी समाज से माफी मांग कर इस मामले को ख़त्म कर सकते थे लेकिन अपने अहंकार में राहुल गाँधी ने समाज और कोर्ट के द्वारा बार-बार समझाने और माफ़ी माँगने के विकल्प को भी नज़रअंदाज़ किया और लगातार ओबीसी समाज की भावना को ठेस पहुँचाई। राहुल गाँधी ने पूरे ओबीसी समाज का अपमान किया। कल अदालत का फैसला आने के बाद भी राहुल गाँधी और कांग्रेस नेता उस बयान को सही ठहराते रहे और अहंकार में डूबे रहे। राहुल गाँधी की सदस्यता उनके अहंकार के कारण गई है। राहुल गाँधी की सदस्यता उनके द्वारा देश के ओबीसी समाज के अपमान और माफी न मांगने के कारण गई है। वे अपने आप को देश से बड़ा समझने की भूल कर बैठे हैं। राहुल गाँधी एक सीरियल ऑफेंडर हैं। वे पहले भी कई झूठी बातें बोल चुके हैं। राफेल मामले पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बारे में ही झूठ बोल दिया था जिसके कारण उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ी थी।

श्री अरुण साव ने कहा कानून सब के लिए बराबर है राहुल गांधी के लिए अलग से कानून और सविधान बनाया जाए? क्र

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का पहला केस साल 2014 में हुआ था। ये केस महाराष्ट्र के भिवंडी कोर्ट में चल रहा है। आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत मानहानि का मामला दर्ज है। राहुल गांधी ने भिवडी में एक भाषण के दौरान संघ (आरएसएस) पर महात्मा गांधी की हत्या का आरोप लगाया था।

2016 में राहुल गांधी के खिलाफ असम के गुवाहाटी में धारा 499 और 500 के तहत मानहानि का केस दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता के मुताबिक राहुल गांधी ने कहा था कि 16वीं सदी के असम के वैष्णव मठ बरपेटा सतरा में संघ सदस्यों ने उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया। उनके इस आरोप से संघ की छवि को नुकसान पहुंचा है। ये मामला भी अभी कोर्ट में पेंडिंग है।

साल 2018 में राहुल गांधी के खिलाफ झारखंड की राजधानी रांची में एक और केस दर्ज किया गया। ये केस रांची की सब डिविजनल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में चल रहा है।

भूपेश बघेल का दांव पर दांव

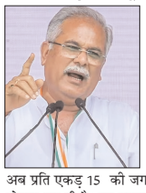

2023 का विधानसभा चुनाव जीतने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दांव पर दांव चल रहे हैं। कहा जा रहा है भाजपा द्वारा एक दांव का तोड़ ढूंढने से पहले ही भूपेश बघेल दूसरा दांव चल देते हैं। भूपेश बघेल ने पहले राज्य में किसानों का धान 2800 रुपए प्रति क्विंटल खरीदने का ऐलान किया। अब प्रति एकड़ 15 की जगह 20 क्विंटल धान खरीदने की घोषणा कर दी है। इस उपहार से किसान गदगद बताए जाते हैं। कहा जा रहा है कि इसका सीधा इम्पैक्ट 2023 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को किसानों का बड़ा साथ मिला था। इस कारण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल किसानों को साध कर रखने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वृक्ष योजना और अन्य तरह से भी किसानों को उपकृत कर कांग्रेस किसानों को अपने से बांधे रखने की रणनीति पर काम कर रही है। छत्तीसगढ़ में 37 लाख से अधिक किसान हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चुनाव से पहले युवाओं को साधने के लिए बेरोजगारी भत्ता का दांव चल चुके हैं। बेरोजगारी भत्ता 2018 के चुनावी घोषणा शामिल था। इस कारण भाजपा ने हल्ला बोल आंदोलन किया था। भूपेश सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं समेत कइयों का मानदेय बढाकर चुनावी चाल चली है। दांव और चाल के नतीजे तो दिसंबर 2023 में ही जनता के सामने आएंगे।

नेताजी अदृश्य

कहा जा रहा है कि ईडी के छापे के बाद कांग्रेस के एक दिग्गज नेता अदृश्य हो गए हैं। कहते हैं इस नेता का सरकारी तंत्र में बड़ा दखल हुआ करता था। अब सरकारी तंत्र से भी इनकी दूरी हो गई है। सरकारी तंत्र से नेताजी के कटाव से राज्य के कुछ मंत्री बड़े खुश बताए जाते हैं। खबर है कि नेताजी कामकाज के लिए मंत्रियों पर हमेशा दबाव बनाए रखते थे। चर्चा है कि नेताजी से ईडी ने तीन चार दौर की पूछताछ कर चुकी है। ईडी ने नेताजी से ही नहीं, बल्कि उनके पुत्र और विशाखापट्नम में रहने वाले भाई को भी पूछताछ के लिए बुला चुकी है। संकेत हैं कि नेताजी जल्दी ही ईडी के हत्थे चढ़ने वाले हैं। शायद इस कारण उन्होंने अदृश्य रहने में ही अपनी भलाई समझी।

अमित शाह के बस्तर दौरे के मायने

कहा जा रहा है कि 2019 के आम चुनाव में भाजपा की हार वाली लोकसभा सीटों पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की नजर है। 2024 में जीत की संभावना तलाशने के लिए इसके पहले वे कोरबा आए थे। अब बस्तर आए हैं। बस्तर में वे दो दिन 24 -25 मार्च को रहे। घोर नक्सली इलाकों में भी सीआरपीएफ के कार्यक्रम के बहाने पहुंचे। 2019 के आम चुनाव में भाजपा छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से 9 जीती थी , लेकिन कोरबा और बस्तर लोकसभा सीटें उसकी झोली में नहीं आई थी। दौरे से जमीनी हकीकत का अंदाजा हो जाएगा। कहते हैं केंद्रीय गृह मंत्री बस्तर से नागपुर होते हुए छिंदवाडा जाएंगे। छिंदवाडा भी कांग्रेस के कब्जे वाली सीट है। छिंदवाडा से मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के पुत्र सांसद हैं।

कही-सुनी

रवि भोई

भाजपा पदाधिकारी मायूस

कहते हैं बस्तर के भाजपा पदाधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलना चाहता था, लेकिन उनके बस्तर प्रवास के दौरान कुछ ही लोग मिल पाए और स्वागत-सत्कार से ज्यादा कुछ न कर पाए। कहते हैं भाजपा पदाधिकारी केंद्रीय गृह मंत्री से भेंटकर उन्हें जमीनी हकीकत से अवगत कराना चाहते थे। इसके लिए वे करीब आधे घंटे का समय चाहते थे, पर ऐसा न हो सका। कहते हैं पदाधिकारी संगठन के कामकाज और तौर-तरीके से लेकर नक्सलवाद के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री के सामने अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहते थे। खबर है कि मुलाक़ात का प्रयास विफल होने से पदाधिकारी मायूस हैं।

समय तक चल गया सत्र

संभावना के उलट छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र निर्धारित समय तक चल गया। सरकारी कामकाज के साथ सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने सदन में अपनी बात रखी , मुद्दे उठाए। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सत्ता पक्ष के विधायक भी इस बार आक्रामक रहे और सरकार ने भी एक्शन के कदम बढाए। सत्ता पक्ष के कुछ विधायकों का सरकार विरोधी सुर चर्चा का विषय रहा। वहीं भाजपा विधायकों की धारा कई भागों में बंटी नजर आई। अलग-अलग सुर-ताल के कारण भाजपा के विधायक सरकार को किसी मुद्दे में उलझा नहीं सके। वाकआउट और कुछ शोर-शराबा कर ही अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। माना जा रहा था भाजपा के तेवर तीखे होंगे और सरकार को कामकाज निपटाने में दिक्कत आएगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। चुनावी साल का यह लंबा सत्र था। मानसून सत्र के दौरान तो चुनावी गहमागहमी का आगाज हो जाएगा।

कौन बनेगा ई ओ डब्ल्यू का प्रमुख ?

राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ई ओ डब्ल्यू) के प्रमुख डी एम अवस्थी 31 मार्च को रिटायर हो जाएंगे, उनकी जगह सरकार किसे ई ओ डब्ल्यू का मुखिया बनाएगी। इस पर कयासबाजी शुरू हो गई है। 1986 बैच के आईपीएस श्री अवस्थी राज्य के डीजीपी रह चुके हैं। अशोक जुनेजा को डीजीपी बनाकर उन्हें पुलिस अकादमी में पोस्ट कर दिया गया था। फिर करीब पांच महीने पहले ही उन्हें ई ओ डब्ल्यू का महानिदेशक बनाया गया। डी एम अवस्थी के रिटायरमेंट के बाद डीजी का एक पद रिक्त हो जाएगा। डीजी बनने की कतार में 1992 बैच के आईपीएस पवनदेव और अरुणदेव गौतम हैं।

नाकाम रायपुर पुलिस

रायपुर में एक सिख संगठन ने अमृतपाल सिंह के समर्थन में रैली निकाल ली और खालिस्तान के समर्थन में नारे लगाए, पर रायपुर की पुलिस को कानों-कान खबर नहीं लगी। दो दिन बाद रायपुर पुलिस जागी और चार लोगों को गिरफ्तार किया। रायपुर पुलिस के पास अच्छा खासा अमला है और उसके पास लोकल इंटेलिजेंस भी है, फिर भी उसके नाक के नीचे देश विरोधियों के समर्थन में लोग आ गए। इस घटना के बाद रायपुर की पुलिस पर सवाल उठने लगे हैं। कहते हैं कुछ महीने पहले कुछ लोगों ने एक देशद्रोही का पोस्टर टाटीबंध इलाके में चस्पा कर दिया था। तब भी रायपुर को हवा नहीं लगी थी और पुलिस ने कोई कार्रवाई करने की जगह मौन रही। चाकूबाजी और अन्य अपराधों में काबू पाने में अब तक नाकाम रायपुर पुलिस पर एक और दाग लग गया है।

अगले हफ्ते सचिव स्तर पर फेरबदल की चर्चा

कहा जा रहा है कि अगले हफ्ते सचिव स्तर पर कुछ फेरबदल संभव है। चर्चा है कि कुछ सचिवों के विभाग इधर-उधर हो सकते हैं। नेहा चंपावत के केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर जाने से गृह विभाग में सचिव का एक पद रिक्त हो गया है। कई विभाग संभाल रहे सचिव और विशेष सचिवों को कुछ हल्का किया जा सकता है। फील्ड में पदस्थ कुछ अफसरों को मंत्रालय में लाने की भी खबर है।

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

प्रदेश में रक्षक ही महिला सुरक्षा के भक्षक बने हुए है - भाजपा

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत ने पुलिस अधिकारी द्वारा बालिका छात्रावास में घुसकर मारपीट और गाली-गलौज की घटना को शर्मनाक बताया। उन्होंने प्रदेश की बालिकाओं की सुरक्षा पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि भूपेश सरकार प्रदेश की महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा करने में पूरी तरह विफल रही है। प्रदेश में कानून के रक्षक ही महिला सुरक्षा के भक्षक बने हुए है। प्रदेश में महिलाओं के प्रति पुलिस प्रशासन और शासन का यह शर्मनाक चेहरा एक बार फिर उजागर हुआ है। उन्होंने कहा कि इस घटना में संबंधित पुलिस अधिकारी पर कार्यवाही तो उसके कृत्यों की प्रतिक्रिया है परंतु मुख्य विषय है की भूपेश बघेल के सरकार में कानून व्यवस्था बेलगाम हो गई है। बोली लगा कर आए अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत ने कहा कि भूपेश सरकार के शासनकाल में महिलाओं के खिलाफ अपराध, यौन दुर्व्यवहार लगातार बढ़ते जा रहे है। यह सरकार महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के प्रति पूरी तरह संवेदनहीन है। यह बालिकाओं की सुरक्षा और आत्मसम्मान पर प्रहार का पहला मामला नहीं है। बल्कि भूपेश शासन में पूरी की पूरी एक परिपाटी चली आ रही है। इससे पूर्व में माना स्थित एसओएस बालिका छात्रावास में एक छात्रा से दुष्कर्म और मामले की लीपापोती का गंभीर मामला सामने आया।

कांग्रेसी कर रहे हैं कोर्ट की अवमानना - सुनील सोनी

रायपुर। रायपुर लोकसभा सांसद सुनील कुमार सोनी ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि श्री राहुल गांधी जी की सजा से कांग्रेसी बौखला गए हैं। कांग्रेस को यह समझना होगा कि यह एक कानूनी प्रक्रिया है, जिसमें 4 वर्षों तक श्री राहुल गांधी जी द्वारा न्यायालय में अपना पक्ष रखा गया और न्यायालय के आदेश के उपरांत ही नियमानुसार उनकी सांसद की सदस्यता समाप्त हुई है। फिर इसमें देश के माननीय प्रधानमंत्रीजी या भारतीय जनता पार्टी कहाँ है ? कांग्रेस के द्वारा अजीबोगरीब वातावरण का निर्माण किया जा रहा है और अशांति फैलाई जा रही है। सांसद श्री सोनी कहा कि श्री राहुल गांधी जी ने पिछड़ा वर्ग का अपमान किया है। गुजरात के मोदी समाज जो कि साहू समाज कहलाता है, उन्हें गाली दी और चोर कहा। घमंड और अहंकार के चलते उन्होंने कोर्ट में क्षमा नहीं मांगा। कांग्रेस और कांग्रेसी नेता पिछड़े वर्ग का अपमान कर रहे हैं। कल कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में तोड़फोड़ की और भाजपा कार्यकर्ताओं का सिर-पैर तोड़ दिया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के लोगों द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में काली स्याही फेंकी गई और पुलिस मूकदर्शक बनकर देखती रही। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सरकार अंग्रेजों से ज्यादा अत्याचार कर रही है, जिसकी हम निंदा करते हैं।

मोदी ने अडानी के भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने सदस्यता खत्म करने का षड़यंत्र रचा - मरकाम

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी ने अडानी के भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने राहुल गांधी की संसद सदस्यता को खत्म करने का षड्यंत्र रचा हैं। सदन से लेकर सड़क तक राहुल गांधी देश की जनता का आवाज उठाते हैं। हर वर्ग के साथ न्याय की बात करते हैं जो मोदी सरकार की असफलताओं को आईना दिखाते हैं और यही बात मोदी सरकार बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि देश की जनता ने भाजपा को 303 सांसद दिए हैं जो देश हित में बात करेंगे लेकिन दुर्भाग्य की बात है यह 303 सांसद मिलकर देश की जनता की आवाज उठाने वाले राहुल गांधी को सदन में बोलने नहीं दिए और उनके सदस्यता समाप्त करा कर उन्हें चुप कराने का षड्यंत्र रचे हैं लेकिन वह असफल रहेंगे। राहुल गांधी जननेता है जो संसद से लेकर सड़क तक किसानों, नौजवानों, महिलाओं की हक की बात करते है, देश की खस्ता हालात और बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, देश की गिरती अर्थव्यवस्था और मोदी सरकार की असफल योजनाओं पर जनता की आवाज उठाते हैं और उठाते रहेंगे।

भाजपाई चोरी ऊपर से सीनाजोरी कर रहे है - कांग्रेस

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा नेताओं द्वारा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय जाना चोरी ऊपर से सीना जोरी है। एक तरफ तो भाजपा कार्यकर्ता कांग्रेस भवन में आकर पथराव करते है, कालिख फेंकते है, तोड़फोड़ करते है, धारदार हथियार से हमला करते है, दूसरी ओर भाजपा के नेता पुलिस पर अनैतिक दबाव बनाने रैली निकालते है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा अध्यक्ष अरुण साव को अपने कार्यकर्ताओं को पत्थरबाजी सिखाने के बजाय लोकतंत्र की मर्यादा में आंदोलन करना सिखाना चाहिए। भाजपा के संस्कार में ही हिंसा और दंगा करने की प्रवृत्ति है उसी का प्रदर्शन भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता अपने सामाजिक, राजनैतिक जिम्मेदारी को समझें तथा अपने उद्दंड कार्यकर्ताओं को संयम और शालीनता का पाठ पढ़ायें। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी यदि उनकी भाषा में जवाब देना शुरू कर देंगे तो बड़ी मुश्किल हो जायेगी। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि कानूनी कार्यवाही और गिरफ्तारी तो आताताई भाजपा नेताओं की होनी चाहिये जिन्होंने राजीव भवन में हमला बोला था।

राहुल गांधी ओबीसी एसटी एससी और आरक्षित वर्गों की हक आवाज उठा रहे- कांग्रेस

रायपुर। खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन, प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष चुन्नी लाल साहू, प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश में ओबीसी, एसटी, एससी और आरक्षित वर्गों की आवाज उठा रहे। मोदी सरकार देश की सरकारी संस्थाओं का निजीकरण कर आरक्षित वर्ग को मिलने वाले आरक्षण के अधिकार से वंचित करने का षड्यंत्र रच रही है जिसे बचाने के लिए कांग्रेस के नेता राहुल गांधी लगातार सदन में और सड़क में आवाज उठा रहे हैं। अडानी ने जिस एलआईसी और एसबीआई के पैसों में घोटाला किया है उस एलआईसी में और एसबीआई में ओबीसी वर्ग, एससी, एसटी और देश के नागरिकों का पैसा जमा है। उसी को बचाने राहुल गांधी जी संसद में मोदी और अडानी के रिश्ते पर सवाल खड़ा किए हैं। भाजपा आरक्षण विरोधी है, यही वजह है कि वह आरक्षित वर्ग को मिलने वाले हक अधिकार को खत्म करने के लिए काम कर रही। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार प्रदेश के आरक्षित वर्ग को 76 प्रतिशत आरक्षण का अधिकार देने के लिए जो विधायक पास कराये हैं उसे राजभवन में भाजपा के नेता रोक रहे हैं। अरुण साव, प्रदेश के ओबीसी वर्ग को बताना चाहिए कि 27 प्रतिशत आरक्षण ओबीसी वर्ग को मिलता जिसे भाजपा राजभवन के पीछे खड़े होकर रुकवाई है यह किस प्रकार से ओबीसी वर्ग का हित है?

मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ समाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण के लिए मोबाईल एप लॉन्च किया

26 से 29 मार्च तक दिया जाएगा प्रशिक्षण

योजना में डोर-टू-डोर होगा सर्वे

रायपुर। महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रीयल पार्क (रीपा) योजना ' के वेब पोर्टल का भी हुआ शुभारंभयोजना में डोर-टू-डोर होगा सर्वेयोजना में डोर-टू-डोर होगा सर्वे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज मुंगेली जिले के सरगांव स्थित खेल मैदान में आयोजित भरोसे के सम्मेलन में चिप्स द्वारा निर्मित छत्तीसगढ़ समाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण हेतु मोबाईल एप का शुभारंभ किया । उन्होंने कहा कि राज्य के सभी वर्गों का उत्थान हमारी शासन की प्राथमिकता है। इसके लिए आधुनिक तकनीकों का उचित उपयोग किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस एप से छत्तीसगढ़ के सभी वर्गों का सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण कर नागरिकों के लाभ हेतु अनेकानेक योजनाएं बनाई जाएगी। सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के लिए चिप्स द्वारा ठाकुर प्यारेलाल राज्य प्रशिक्षण संस्थान, निमोरा में 25 मार्च से 29 मार्च 2023 तक राज्य भर के 200 से अधिक मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण दिया जायेगा।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस अवसर पर चिप्स द्वारा निर्मित महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रीयल पार्क (रीपा) योजना के वेबसाईट का भी शुभारंभ किया। इस पोर्टल में रीपा योजना के समस्त हितग्राहियों की पूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। इस संबंध में जानकारी दी गई कि रीपा योजना से ग्रामीण उद्यमियों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा का सामान अवसर मिलेगा। साथ ही छत्तीसगढ़ के स्थानीय उत्पाद जैसे हरबल गुलाल, गोबर निर्मित प्राकृतिक पेंट आदि के लिए बाजार भी उपलब्ध होगा। फलस्वरूप राज्य के स्थानीय नागरिकों को उनके घर के निकट गाँव में ही रोजगार प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। चिप्स द्वारा निर्मित मोबाईल एप का विवरण देते चिप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अमिताभ शर्मा ने बताया कि यह ऐप चिप्स द्वारा विकसित किया गया है।

भाजपा ने एकपक्षिय कार्यवाही के विरोध पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव कर ज्ञापन दिया

द्वेष पूर्ण कार्यवाही स्वस्थ लोकतंत्र के लिए हानिकारक : अरुण साव

रायपुर। कांग्रेस नेता राहुल गाँधी को न्यायालय द्वारा सजा दिए जाने के बाद से ही दिशाहीन उग्र आंदोलन कर रही है इसी कड़ी में कांग्रेसियों द्वारा कल भाजपा कार्यालय में जमकर उत्पात मचाया गया कार्यालय में घुसने का प्रयास , बिना सूचना एकात्म परिसर के समक्ष पुतला दहन और पोस्टरों पर कालिख भी फेंका गया तब तक पुलिसिया कार्यवाही शून्य रही उसके पश्चात भाजयुमो कार्यकर्ताओ ने विरोध स्वरूप कॉंग्रेस कार्यालय के बाहर विरोध करने पहुँचे जहाँ कांग्रेसीयो ने पूर्व तैयारी के साथ भाजयुमो कार्यकर्ताओं पर जमकर पथराव किया एवं लाठी डंडों से प्रहार किया जिसमें भाजयुमो जिला अध्यक्ष सहित दर्जन भर कार्यकर्ता घायल हो गए 3 लोगो को अति गंभीर चोट आई जिन्हें आनन फानन में अस्पताल भर्ती करवाया गया जहाँ डक्टरों ने बताया कि एक कार्यकर्ता का पैर बुरी तरह से टूट गया है एवं एक का सिटी स्कैन कराने पर सर पर खून का थक्का जमना पाया गया जिसका इलाज डी. के.अस्पताल में जारी है भाजपा के वरिष्ठ नेताओं द्वारा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव , वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल, रायपुर लोकसभा सांसद सुनील सोनी, पूर्व मंत्री राजेश मूणत, पूर्व विधायक द्वय श्रीचन्द सुंदरानी, नंदकुमार साहू , संजय श्रीवास्तव के नेतृत्व में पहले रायपुर शहर जिला भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक हुई जिसके पश्चात पैदल मार्च करते हुए भाजपा नेता पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुँचे एवं जमकर नारेबाजी की गई एवं कांग्रेसियो द्वारा किए गए हमले के खिलाफ उचित कानूनी कार्यवाही की मांग का ज्ञापन सौंपा गया।

एकात्म परिसर में कार्यकर्ताओ को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि 4 साल से न्यायलय में मामला लंबित था परंतु राहुल गांधी का गैर जिम्मेदाराना रवैया नही बदला उन्होंने 4 वर्ष में उस प्रतिवाद जिसमे उन्होंने जातिगत अपमान जनक टिप्पणी की थी पर तेली समाज और ओ.बी.सी समाज से माफी नही माँगी। उन्होंने कहा कि सरकार है तो आपको दादागिरी का लाइसेंस नही मिल जाता लोकतंत्र सभी को समान अधिकार देता है परंतु पुलिस प्रशासन तो जैसे सरकार का एजेंट बनकर कार्य कर रहा है मैं सभी अधिकारियों को आगाह करता हूँ कि इस तरह एजेंट की तरह कार्य करना बंद करे ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें समय बदलते देर नही लगती इस तरह की द्वेष पूर्ण कार्यवाही स्वस्थ लोकतंत्र के लिए हानिकारक है।

राहुल सदस्यता रद्द होने पर हुए हंगामे को लेकर भाजपा नेताओं के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया

कांग्रेस नेताओं द्वारा भाजपा कार्यालय के सामने हंगामा किया गया और भाजपा नेताओं द्वारा कांग्रेस कार्यालय के सामने हंगामा किया गया और पुलिस अधिकारियों के साथ की गई झूमाझटकी के विरोध में आखिर पुलिस ने कांग्रेस और भाजपा नेताओं के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर ही लिया। कांग्रेस नेताओं और पुलिस अधिकारियों की शिकायत पर पुलिस ने भाजपा नेताओं संजय वास्तव, अमित साहू, तुषार चोपड़ा, गुंजन प्रजापति सहित करीब 60 लोगों के विरुद्ध धारा 147 148 149 294 323 341 427 506 186 और धारा 353 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है..

कांग्रेस को तानाशाही विरासत में मिली है - बृजमोहन अग्रवाल

वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय के समक्ष मीडिया को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार और प्रशासन को जमकर आड़े हाथ लिया उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज में अंधेर नगरी चौपट राजा वाली प्रथा चल रही है चोट हमारे कार्यकर्ताओ को आई गंभीर रूप से भाजपा कार्यकर्ता घायल हुए 3 अभी भी अस्पताल में जूझ रहे हैं पर कार्यवाही भी गई तो भाजपा कार्यकर्ताओं पर कॉंग्रेस को तानाशाही विरासत में मिली है हम 24 घण्टे तक कार्यवाही की प्रतीक्षा करेंगे अन्यथा हम प्रदेश भर में उग्र आंदोलन करेंगे। लोकसभा सांसद सुनील सोनी ने कहा कि कांग्रेस के लोग पूरे देश मे अशांति फैला रहे हैं ।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.